



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14.]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2003/पौष 23, 1924

No. 14]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2003/PAUSA 23, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2003

प्रारंभिक निष्कर्ष

विषय :—चाइनीज ताइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) से कास्टिक सोडा के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 14/39/2002-डीजीएडी.—भारत सरकार 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए,

क. प्रक्रिया

1. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :—

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकारी भी कहा गया है) का उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स अल्काली मैनुफैक्चरर्स एसोशिएशन ऑफ इंडिया

(ए०एम०ए०आई०) (जिसे इसके पश्चात याचिकाकर्ता कहा गया है) से एक लिखित याचिका प्राप्त हुई है जिसमें चाइनीज ताइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) (जिन्हें इसके पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल से अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आमतौर पर कास्टिक सोडा (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है। यह याचिका मैसर्स डी०सी०डब्ल्यू० लिमिटेड, मुंबई, मैसर्स गुजरात अल्कालीज एण्ड कैमिकल लिमिटेड, बदोदरा, गुजरात, मैसर्स सर्वे कैमिकल्स इन्डस्ट्रील लिमि०, मुम्बई, मैसर्स ग्रासिम इन्ड० लिमि०, नगदा, मध्य प्रदेश, मैसर्स सिएल कैमिकल कम्पलैक्स, पटियाला, पंजाब मैसर्स बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लिमि० झारखंड, मैसर्स जयश्री कैमिकल्स लिमि०, उड़ीसा, मैसर्स आंध्रा शुगर लिमि० तनाकू, डी०सी०एम०श्रीराम, नई दिल्ली मैसर्स इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमि०, बदोदरा, मैसर्स स्टेडर्ड अल्काली मुम्बई और मैसर्स डी०सी०एम० श्रीराम कन्सोलिडेटेड लि०, नई दिल्ली द्वारा समर्थित थी।

(ii) याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन की प्रारंभिक जांच करने पर कुछ कमियां दृष्टिगत हुईं जिन्हें बाद में याचिकाकर्ता द्वारा सुधार लिया गया। अतः यह याचिका उचित तौर पर प्रलेखित की गई मानी गई।

(iii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर चाइनीज ताइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) से संबद्ध वस्तु के आयात के प्रति जांच शुरू करने का निर्णय लिया। प्राधिकारी ने नियमों के उपनियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्यवाही शुरू करने से पहले पाटन के आरोप पत्र की प्राप्ति के बारे में नई दिल्ली में चाइनीज ताइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के दूतावासों को सूचित किया।

(iv) प्राधिकारी ने दिनांक 8 अक्टूबर 2002 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा चाइनीज ताइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु, जिन्हें कस्टम टेरिफ एक्ट 1975 (आई०टी०सी का 28151101, 28151102 और 28151200) की अनुसूची -1 के कस्टम

कोड 281511 और 281512 के तहत वर्गीकृत किया गया है, के आयात के बारे में पाटनरोधी कार्रवाई आरंभ की गई ।

(v) प्राधिकारी ने नियम 6(2) के अनुसार उक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात निर्यातकों (जिनका ब्यौरा याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को भेजी और उन्हें इसके जारी होने के चालीस दिनों के भीतर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया ।

(vi) प्राधिकारी ने उक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति भारत में संबध वस्तु के ज्ञात सभी आयातकों (जिसका ब्यौरा याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को भेजी और उन्हें इसके जारी होने के चालीस दिनों के भीतर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई ।

(vii) केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क (सी बी ई सी) से अनुरोध किया गया कि वे जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में दिए गए संबद्ध वस्तु के आयातों का ब्यौरा दें ।

(viii) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को भेजी । जब कभी भी अनुरोध प्राप्त हुए अन्य हितबद्ध पक्षों को याचिका के अगोपनीय अंशों की प्रति भी उपलब्ध कराई गई ।

(ix) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को संगत सूचना प्राप्त करके के लिए एक प्रश्नावली भेजी:-

1. मैसर्स बीएएसएफ अंटवर्पन एनवी, अंटवर्पन, बेलजियम
2. मै0 बेयर शेल आईसोसाइनेट, एन0बी0 अंटवर्पन, बेलजियम
3. मै0 सोलवे एस0ए0 अंटवर्पन, बेलजियम
4. मै0 अशाहिमस कैमिकल्स, अनयर, इंडोनेशिया
5. मै. कलानी केरटस, ईस्ट कलीमन्तन, इंडोनेशिया
6. मै0 मुसी पल्प मिल्स, प्राबुरलिन साउथ, इंडोनेशिया

7. मै० एसीमोन्ट, बुसी, इटली
8. मै० इनीकैम स्पा, इसीमिनी, इटली
9. मै. कैशी कैमिकल्स कं. लि., ताइवान
10. मै. चेंग ताई कैमिकल्स वर्क्स, चाइनिज ताइपेई
11. मै. चेंग टोंग कैमिकल्स कं. चाइनिज, ताइपेई

(x) नियम 6(2) के अनुसार नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को जांच शुरू होने के बारे में सूचित किया गया था और साथ ही उनसे यह अनुरोध भी किया गया था कि वे अपने देश के सभी संबद्ध निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय के भीतर देने की सलाह दें। नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के दूतावासों को पत्र, याचिका और ज्ञात निर्यातकों को भेजी गई प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी गई थी।

(xi) नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ता संघों को एक प्रश्नावली भेजी गई थी।

1. मैसर्स अभय कैमिकल्स लिमि०, बडौदा
2. मैसर्स अलब्राइट विल्सन कैमिकल्स लिमि०, मुम्बई
3. मै० अरविंद मिल्स लिमि०, अहमदाबाद
4. मै० बिरला सैलुलोज लिमि०, भडौच
5. मै० सैन्ट्रल पल्प मिल्स लिमि०, नई दिल्ली
6. मै० दीपक नाइट्रीट लिमि०, नन्दसराय
7. मै० गोदरेज शोपस लिमि०, मुम्बई
8. मै० गुजरात इलै० बोर्ड, बडोदरा
9. मै० गुजरात नर्मदे फल्टीलाइजर कं० लिमि०, भडौच
10. मै० गुजरात स्टेट फल्टीलाइजर एंड कैमिकल्स लिमि., बडोदरा
11. मै० हिन्दुस्तार लीवर लिमि०, मुम्बई

12. मै0 आईसीआई इंडिया लिमि., मुम्बई
13. मै0 इंडियन फारमर फल्टीलाइजर कारपो0 लिमि, गांधीनगर
14. मै0 इंडियन आयल कारपोरेश लिमि0, बडोदरा
15. मै0 इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो0 लिमि., बडोदरा
16. मै0 जॉयसिथ डाइकेमिकल्स लिमि., मुम्बई
17. मै0 लिंक फार्मा लिमि., बडोदरा
18. मै0 मेघमनी आरगेनिक लिमि, अहमदाबाद
19. मै0 नर्मदा पेट्रोकेमिकल्स लिमि., भडौच
20. मै0 निरमा लिमि0, अहमदाबाद
21. मै0 पैब्स कैमिकल्स (पी) लिमि, बडोदरा
22. मै0 रामा न्यूज प्रिंट एंड पेपरर्स लिमि., सूरत
23. मै0 रुबामिन लिमि., बडोदरा
24. मै0 सैब्रो आरगेनिक लिमि., मुम्बई
25. मै0 टोरेट गुजरात बायो-टेक लिमि., बडोदरा
26. मै0 ट्रांसपैक इस्ट्री. लिमि., बडोदरा
27. मै0 नेशनल अल्युमिनियम कम्प. लि., भुवनेश्वर
28. मै0 साइनाइडेट एंड कैमिकल्स कम्प., मुम्बई
29. मै0 डिमोसा कैमिकल्स लिमि., मुम्बई
30. मै0 ट्रांसपैक सिलौक्स इस्ट्री0 लिमि., बडोदरा
31. मै0 दीपक नाईट्रेट लिमि0, पुणे
32. मै0 हित्सु इस्ट्री. लिमि., गुजरात
33. मै0 अदानी एक्पोर्ट लिमि., अहमदाबाद
34. मै0 अदानी विलमर लिमि0, गुजरात
35. मै0 लिब्रा फोम्स , गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0
36. मै0 श्री रामचन्द्र स्ट्रा प्रोडक्ट लिमि., मुरादाबाद, उ0प्र0
37. मै0 बिलाग इन्ट्री. प्रा. लिमि., गुजरात

38. मै० दौराला आरगेनिक लिमि., नई दिल्ली
39. मै० सी जे साह एंड कं., मुम्बई
40. मै० हरीश कुमार एंड कंपनी, मुम्बई
41. मै० लम्पोरा कैमिकल्स एंड इन्ट्री. लिमि., गुजरात
42. मै० हिन्दुस्तान इंक एंड रेजिन लिमि०, गुजरात

प्रश्नावली/अधिसूचना के प्रति निम्नलिखित निर्यातकों/आयतकों द्वारा उत्तर/सूचना दायर की गई थी:-

1. मैसर्स सोलवे ब्रूसेल्स, बेलजियम

प्रश्नावली/अधिसूचना के प्रति निम्नलिखित निर्यातकों/उपयोगकर्ता संघों द्वारा उत्तर/सूचना दायर की गई थी:-

1. मैसर्स नालको, भुवनेश्वर
2. मैसर्स हिन्द लीवर केमिकल्स लि०, मुंबई
3. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि०, मुंबई

(xii) याचिकाकर्ताओं से क्षति के बारे में सूचना मांगी गई थी जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई। निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों के क्षति के मापदण्ड दिए गए थे:-

1. मै० डी.सी.डब्ल्यू. लिमि., मुम्बई
2. मै० गुजरात अलकालिस एंड कैमिकल्स लिमि., बडोदरा
3. मै. सर्च कैमिकल्स इन्ड्र. लिमि., मुम्बई।
4. मै. ग्रासिम इन्स्ट्री. लिमि., नागदा (मध्य प्रदेश)
5. मै. एस०आई०ई०एल० कैमिकल्स लिमि., पंजाब
6. मै० बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लिमि., बिहार
7. मै० जयश्री कैमिकल्स लिमि., उड़ीसा

8. मै0 आन्ध्रा शुगर लिमि., तनाकू
9. मै0 इंडियन पेट्रो. कैमिकल्स कारपो. लिमि., दाहेज

(xiv) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को अपने द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पक्षों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुला रखा ।

(xv) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर सामान्यतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण के नियमों के आधार पर उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने व उसका विक्रय करने की लागत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का भी विश्लेषण किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम का पाटनरोधी शुल्क, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा । निम्नलिखित कम्पनियों के उत्पादन के आंकड़ों की लागत के बारे में उचित तरीके से विचार किया गया व उनकी जांच की गई:-

1. मै0 डीसीडब्ल्यू लिमि., मुम्बई
2. मै0 गुजरात अलकालिस एंड कैमिकल्स लिमि., बड़ोदरा
3. मै0 सर्व कैमिकल्स इन्ड्र. लिमि., मुम्बई ।
4. मै0 ग्रासिम इस्ट्री. लिमि., नागदा (मध्य प्रदेश)
5. मै0 एस0आई0ई0एल0 कैमिकल्स लिमि., पंजाब
6. मै0 बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लिमि., बिहार
7. मै0 जयश्री कैमिकल्स लिमि., उड़ीसा
8. मै0 आन्ध्रा शुगर लिमि., तनाकू
9. मै0 इंडियन पेट्रो. कैमिकल्स कारपो. लिमि., दाहेज

(xvi) **** इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना प्रदर्शित होती है जिसे नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा ऐसा ही माना गया है ।

(xvii) उत्तर देने की अंतिम तिथि 28 नवंबर, 2002 थी। हितबद्ध पक्षों के अनुरोध पर 10 दिसंबर, 2002 तक का और समय विस्तार दिया गया। दिनांक 18 दिसंबर 2002 को एक आयातक - मैसर्स नालको से अपूर्ण उत्तर प्राप्त हुआ, जिस पर नामित प्राधिकारी द्वारा विचार भी किया गया।

(xviii) 1 जनवरी से 30 सितम्बर, 2002 तक की अवधि अर्थात् जांचावधि के लिए जांच शुरू की गई थी।

(xix) याचिकाकर्ता से क्षति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगे गये थे, जिन्हें प्रस्तुत किया गया।

(xx) प्राधिकारी ने जिस सीमा तक उचित समझा उस सीमा तक घरेलू उद्योग की तत्स्थाने (आन-द-स्पॉट) जांच की।

(xxi) व्यापक परिचालन के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने की सूचना की प्रतियां फिक्की, सीआईआई, एसोचैम आदि को भी भेजी गई।

ख. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

1. उत्पादकों के विचार

क. विचाराधीन उत्पाद

(i) भारतीय बाजार में पाटे जा रहे उत्पाद का नाम सोडियम हाइड्रोआक्साइड है जो सामान्यतया कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है। रसायनिकतौर पर कास्टिक सोडे को एनओओएच के रूप में जाना जाता है। यह एक अकार्बनिक रसायन है जिसे कास्टम टेरिफ एक्ट के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत किया गया है। कास्टिक सोडा एक साबुन जैसा, बहुत ही क्षारीय गन्धहीन तरल पदार्थ है जिसे विविध औद्योगिक क्षेत्रों में या तो एक कच्चे माल के रूप में या एक सहायक रसायन के रूप में व्यापकतौर पर प्रयोग में लाया जाता है। इसे मुख्यतया गुदा (पल्प) और कागज बनाने, न्यूजप्रिंट, विसकोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्मुनियम, काटन, टेक्सटाइल्स, टाइलेट और लांड्री सोप, डिटरजेंट, डाइस्टफ, ड्रग और फरमास्यूटिकल्स, वनस्पति बनाने, पेट्रोलियम रिफाइनिंग करने आदि

में उपयोग में लाया जाता है। कास्टिक सोडा दो आकार में बनाया जाता है - सज्जीदार पानी (ली) और ठोस आकार में। इसका ठोस आकार; फ्लेक्स, प्रिल्स, ग्रेन्यूल्स अथवा किसी अन्य रूप में हो सकते हैं। कास्टिक सोडे के सभी आकार मौजूदा याचिका की विषय वस्तु हैं।

कास्टिक सोडा, शरीर के तन्तुओं के साथ सम्पर्क पर आने पर जलन पैदा करता है। नेत्रों के सम्पर्क पर आने पर यह उन्हें गम्भीर क्षति करता है, निगल जाने पर यह शरीर को गम्भीर क्षति पहुंचाता है। कास्टिक सोडा मिस्ट, नाक और गले में थोड़ी देर तक चुम्बन भरी अनुभूति देता है। यह तेज एसिड के साथ उबलाव की स्थिति के तहत बहुत ही उग्र रूप से प्रतिक्रिया करता है।

(ii) कास्टिक सोडा एक ऐसा मूलभूत उत्पाद है जिसे व्यापकतौर पर विविध औद्योगिक क्षेत्रों में या तो कच्चे माल के रूप में अथवा सहायक रसायन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, इसे मुख्यतया पल्प और कागज बनाने, न्यूजप्रिंट, बेरीकोज यार्न, स्टेपल फाइबर, अलुमिनियम, काटन, टेक्सटाइल्स, टाइलेट और लांड्री सोप, डिटरजेंट डाइस्टफ, ड्रग्स और फारमास्यूटिकल्स, वनस्पति बनाने, पेट्रोलियम शुद्धिकरण करने आदि में उपयोग में लाया जाता है।

(iii) कास्टिक सोडे के उत्पादन के लिए विश्वभर में तीन प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। भारतीय उद्योग इन सभी तीन प्रक्रियाओं को उपयोग में लाते हुए कास्टिक सोडे का उत्पादन कर रहा है। ये तीन प्रक्रियायें इस प्रकार से हैं-

1. मरक्युरी सेल प्रोसेस
2. डाइअप्रैम प्रोसेस
3. मेमब्रेन प्रोसेस

मरक्युरी सेल्स प्रोसेस:

मरक्युरी सेल प्रोसेस के विनिर्माण की प्रक्रिया में टेटोनियम धातु के एनोड्स को कैथोड की तरह एनोडसैड मरक्युरी के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। संतृप्तकों (सैचुरेटर्स) में नमक मिलाया जाता है जहां ब्राइन (लवण जल) डिक्लोरिनेशन टावर से कम होता हुआ लवण जल

(डिप्लीटड ब्राइन), संतृप्त होने के लिए आता है। कम होते हुए लवण जल की मात्रा, सोडियम क्लोराइड (एन०ए०सी०एल०) का लगभग 260 जी०पी०एल० होती है। कम होता हुआ लवण जल, उन संतृप्तकों (सैचुरेटर्स) में प्रविष्ट होता है जो नमक से भरे होते हैं, और इसके बाद यह लवण जल, सोडियम क्लोराइड की 310 जी०पी०एल० की सांद्रता से संतृप्त होने के बाद दूसरी तरफ को चला जाता है। संतृप्तकों (सैचुरेटर्स) से लवण जल दो शोधक यंत्रों (प्यूरीफायर्स) में जाता है, जहां लाइम (कैल्शियम हाइड्रो आक्साइड) और सोडियम कारबोनेट को मिलाया जाता है ताकि सैटलर्स में जाने से पहले इसकी अशुद्धताएं अलग हो जाएं और शुद्ध किया हुआ लवण जल सैटल से शुद्धित ब्राइन टैंक में चला जाए। अलग की हुई उन अशुद्धियों को जिन्हें सैटलर्स के तले में एकत्रित किया जाता है, तले के वाल्व (कपाट) से बाहर निकाला जाता है और उन्हें स्लज पिट में फेंका जाता है जहां इसे बैठने दिया जाता है और इसमें से सुपरनेटेन्ट लवण जल (ब्राइन) को निकाल लिया जाता है।

उस शुद्धित लवण जल (ब्राइन) को जिसे टैंक में एकत्रित किया जाता है, फिल्टर्स के माध्यम से शुद्ध किए हुए ब्राइन स्टोरेज टैंक में पम्प किया जाता है। इस स्टोरेज टैंक से शुद्ध ब्राइन को 11 मीटर से अपर की ऊंचाई पर स्थित ओवरहेड टैंक में पम्प किया जाता है। इस ओवरहेड टैंक से शुद्ध ब्राइन को निरन्तर सैल्स के सम्पोषण के लिए सैल हाउस में भेजा जाता है जहां एलेक्ट्रोलीटिक प्रोसेस द्वारा सोडियम क्लोराइड को सड़ाया जाता है और इससे कार्बिक सोडा और क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस बनती हैं। हीट एक्सचेंजर्स के माध्यम से इस कार्बिक सोडा को कार्बिक सोडा स्टोरेज टैंक में पम्प किया जाता है।

उस अपघटित लवण जल (डिकम्पोज्ड ब्राइन) को डिप्लीटड ब्राइन कहा जाता है जो सैल्स से आता है। जब यह ब्राइन, सैल्स से गुजरता है तो इसकी सोडियम क्लोराइड की सांद्रता 310 जी०पी०एल० से घटकर 260 जी०पी०एल० हो जाती है। इस डिप्लीटड ब्राइन को जिसमें कि क्लोरीन की उतनी ही मात्रा होती है, तब ब्राइन डिक्लोरिनेशन टावर में भेजा जाता है जहां नैक्यूम डिक्लोरिनेशन द्वारा इसमें से क्लोरीन गैस को हटाया जाता है और इसके पश्चात् इसे मूलनिरूपण के लिए सैचुरेटर्स में भेजा जाता है। उस क्लोरीन गैस को जिसे सैलून में सृजित किया जाता है, ब्लोअर द्वारा क्लोरीन कूलिंग क्षेत्र में भेजा जाता है, यहां गैस को ठंडा किया जाता है और अधिकतर

नमी को दूर किया जाता है। ठंडा होने के पश्चात् गैस को क्लोरीन शुष्कीकरण के लिए भेजा जाता है जहां शेष नमी को शुष्कीकरण टावर में सल्फरिफ एसिड के साथ क्लोरीन गैस के साथ संपर्क करवा कर दूर किया जाता है। शुष्कीकरण टावर से बाहर आने वाली गैस, नमी रहित होती है इसके बाद इसे क्लोरीन कम्प्रेसर में भेजा जाता है जहां इसे लगभग 3 किलोग्राम/सेमी 2 के दबाव पर दबाया (कम्प्रेस) जाता है। इसके बाद इसे लिक्विफैक्शन में भेजा जाता है जहां इसे 10 डिग्री सेलसियस के तापमान पर तरलीकृत (लिक्विफाइ) किया जाता है। इसके बाद इस तरलीकृत गैस को लिक्विड क्लोरीन स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है।

उस हाइड्रोजन गैस को जिसे सेल हाउस में भी सृजित किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होल्डर में एकत्रित किया जाता है।

गैस होल्डर से हाइड्रोजन 1 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड संयंत्र में भेजा जाता है जहां इस गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भट्टी में जलाया जाता है। भट्टी से 33% हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अंतर्वर्ती हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिसीवर टैंक में चली जाती है जहां से इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है।

मेमब्रेन सेल में सेल एलीमेन्ट्स होते हैं। प्रत्येक सेल एलीमेन्ट अनोड और कैथोड के जमाव से बने होते हैं और इनके बीच में एक मेमब्रेन सेल रहती हैं।

वह शुद्ध लावण जल जिसे इलेक्ट्रोलिटिक स्थितियों के तहत इनलेट नोजल के माध्यम से अनोड कम्पार्टमेंट में भेजा जाता है, सोडियम (एन.ए.)+ और क्लेम: आयन्स (सीएल) में विघटित हो जाता है। सोडियम (एन.ए.)+ के आयन्स, मेमब्रेन एलीमेन्ट के माध्यम से कैथोड कम्पार्टमेंट में जाते हैं। एनोड कम्पार्टमेंट से क्लेम: आयन्स सी.एल.2 गैस बनाते हैं।

यहां इनलेट नोजल के माध्यम से पतला किया हुआ कास्टिक, कैथोड, कम्पार्टमेंट में भेजा जाता है। यहां पानी (एच 2 ओ) एच+ और ओ०एच० आयन्स में विघटित हो जाते हैं और ओ०एच० आयन्स, सोडियम (एन०ए०)+ आयन्स (अनोड कम्पार्टमेंट से) के साथ जुड़ जाते हैं और इससे कैथोड कम्पार्टमेंट से हाइड्रोजन के रूप में विकसित कास्टिक एच+ आयन्स पैदा होती है। सेल से प्राप्त हाइड्रोजन को ठंडा किया जाता है और इसे हाइड्रोजन (एच 2) गैस होल्डर में भेजा जाता है।

सेल से प्राप्त होने वाली क्लोरीन को ठंडा किया जाता है और इसे क्लोरीन ट्रीटमेंट खंड में भेजा जाता है। इसके बाद ड्राई क्लोरीन को दबाया (कम्प्रेस) जाता है और इसे लिक्वीफायर में भेजा जाता है जहां इसका तरलीकरण किया जाता है। इस क्लोरीन को गुरुत्वाकर्षण द्वारा लिक्विड क्लोरीन स्टोरेज टैंक में लिया जाता है और बिक्री के लिए एक टन की क्षमता वाले कंटेनर में पैक किया जाता है। इसके अलावा, उस अतिरिक्त गैस, जिसका तरलीकरण नहीं किया गया है, को एच₂सी₂एल₂ सैक्शन में भेजा जाता है, जहां सी₂एल₂ 2 गैस को हाइड्रोजन के साथ जलाया जाता है और लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए पानी के साथ मिलाया जाता है।

मेमब्रेन प्रोसेस:

मेमब्रेन प्रोसेस के साथ कास्टिक सोडा बनाने की प्रक्रिया में अपेक्षित मुख्य सामग्री नमक है और अन्य प्रमुख आदान विद्युत है।

प्रोसेस प्लांट से वापस आये पतले लवण जल (नमक घोल) को नमक मिलाकर सैचुरेटर्स में, संतृप्त किया जाता है। इस लवण जल को प्राथमिक और द्वितीयक ब्राइन ट्रीटमेंट सैक्शन में अशुद्धियों को दूर करने के लिये उपचारित किया जाता है। लवण जल की अपेक्षित अति परिशुद्धता को आइन एक्सचेन्ज कालम्स के द्वारा द्वितीयक ब्राइन ट्रीटमेंट में प्राप्त किया जाता है। इस अति परिशुद्ध लवण जल (ब्राइन) को मेमब्रेन सेल के एनोड कक्ष में भेजा जाता है। इस सेल में दो कक्ष होते हैं जो मेमब्रेन द्वारा विभाजित रहते हैं। एक कक्ष कैथोड और दूसरा कक्ष एनोड के रूप में जाना जाता है। पतले कास्टिक को कैथोड कक्ष में डाला जाता है मुख्य उत्पाद के रूप में सांद्रित कास्टिक को सेल से एकत्रित किया जाता है। सेल से प्राप्त पतले लवण जल को डिक्लोरिनेशन के उपरान्त वापस सैचुरेटर्स में भेजा जाता है।

मेमब्रेन की चुनिदा आयन विनियम विशेषता को उपयोग में लाते हुए आयन एक्सचेन्ज मेमब्रेन प्रोसेस द्वारा मेमब्रेन सेल में कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन को पैदा किया जाता है।

मेमब्रेन सेल में सेल एलीमेंट्स होते हैं। प्रत्येक सेल एलीमेंट्स एनोड और कैथोड के जुड़ाव से बने होते हैं जो मेमब्रेन सेल द्वारा विभाजित रहते हैं।

मेम्ब्रेन सेल में सेल एलीमेंट्स होते हैं। प्रत्येक सेल एलीमेंट अनोड और कैथोड के जमाव से बने होते हैं और इनके बीच में एक मेम्ब्रेन सेल रहती है।

वह शुद्ध लावण जल जिसे इल्क्ट्रोलाइटिक स्थितियों के तहत इनलेट नोजल के माध्यम से अनोड कम्पार्टमेंट में भेजा जाता है, सोडियम (एन.ए.)⁺ और क्लेम: आयन्स (सीएल) में विघटित हो जाता है। सोडियम (एन.ए.)⁺ के आयन्स, मेम्ब्रेन एलीमेंट के माध्यम से कैथोड कम्पार्टमेंट में जाते हैं। एनोड कम्पार्टमेंट से क्लेम: आयन्स सी.एल.2 गैस बनाते हैं।

यहां इनलेट नोजल के माध्यम से पतला किया हुआ कास्टिक, कैथोड, कम्पार्टमेंट में भेजा जाता है। यहां पानी (एच 2 ओ) एच⁺ और ओ⁰एच⁰ आयन्स में विघटित हो जाते हैं और ओ⁰एच⁰ आयन्स, सोडियम (एन⁰ए⁰)⁺ आयन्स (अनोड कम्पार्टमेंट से) के साथ जुड़ जाते हैं और इससे कैथोड कम्पार्टमेंट से हाइड्रोजन के रूप में विकसित कास्टिक एच⁺ आयन्स पैदा होती है। सेल से प्राप्त हाइड्रोजन को ठंडा किया जाता है और इसे हाइड्रोजन (एच 2) गैस होल्डर में भेजा जाता है।

सैल से प्राप्त होने वाली क्लोरीन को ठंडा किया जाता है और इसे क्लोरीन ट्रीटमेंट खंड में भेजा जाता है। इसके बाद ड्राई क्लोरीन को दबाया (कम्प्रेस) जाता है और इसे लिक्वीफायर में भेजा जाता है जहां इसका तरलीकरण किया जाता है। इस क्लोरीन को गुरुत्वाकर्षण द्वारा लिक्विड क्लोरीन स्टोरेज टैंक में लिया जाता है और बिक्री के लिए एक टन की क्षमता वाले कंटेनर में पैक किया जाता है। इसके अलावा, उस अतिरिक्त गैस, जिसका तरलीकरण नहीं किया गया है, को एच⁰सी⁰एल⁰ सैक्शन में भेजा जाता है, जहां सी⁰एल⁰ 2 गैस को हाइड्रोजन के साथ जलाया जाता है और लिक्वूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए पानी के साथ मिलाया जाता है।

(iv) कास्टिक सोडा के विनिर्माण के लिये यद्यपि इन सभी प्रौद्योगिकियों को भारत में उपयोग में लाया जा रहा है तथापि मरक्युरी सैल प्रौद्योगिकी और मेम्ब्रेन सैल प्रौद्योगिकी को व्यापक तौर पर भारत में अपनाया जा रहा है।

(v) भारतीय कास्टिक सोडा उद्योग बड़े पैमाने पर भारत में कास्टिक सोडा की सारी मांग को पूरा करने में सफल रही है। भारतीय उद्योग वर्ष 1975 से अपनी मांग में आत्मनिर्भर रहा है। जैसाकि पिछले पैसे में उल्लेख किया गया है। कास्टिक सोडा आयातों की उस सूची में रहा है जिसे ओजीएल के तहत अनुमत किया गया है, विशेषकर 1980-81 से वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिये। तथापि, भारतीय उद्योग की मूल्य निर्धारण की नीति के कारण आयात सीमित रहे। चाइनीज ताइपे, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) में उत्पादकों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता उनके खुद के देश में मांग की अपेक्षा काफी अधिक है। इसके अलावा, कई अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के साथ संबद्ध देशों में उत्पादक भारत को निर्यात करना आकर्षक समझ रहे हैं। इन देशों में अत्याधिक क्षमता से उत्पादकों पर बहुत ही दबाव पड़ रहा है कि वह अपने देश से बाहर बाजार खोजें। परिणामस्वरूप, चाइनीज ताइपे, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के निर्यातकों ने भारत को निर्यात किये जाने के लिये बहुत ही कम मूल्य उद्धृत किये हैं। इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि इन देशों के उत्पादकों ने कई बार भारत को सीधे ही अपनाई सप्लाई के लिये प्रस्ताव नहीं किया है। इन देशों के मूल से कास्टिक सोडा की सप्लाई के लिये तीसरे देशों में व्यापारियों द्वारा काफी मात्रा प्रस्तावित की गई है। इन व्यापारियों द्वारा किये जा रहे प्रस्ताव में जाहिव राना तौर पर इन व्यापारियों ने अपना मार्जिन भी शामिल किया होगा। अतः उन देशों में उत्पादकों द्वारा उद्धृत किये गये मूल्य अभी भी कम बने हुए हैं। याचिकाकर्ताओं का विश्वास है कि प्रस्तावित किये जा रहे ये मूल्य, उत्पादन के सहबद्ध किये गये मूल्य से काफी नीचे हैं। इस प्रकार चाइनीज ताइपे, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के निर्यातकों ने भारतीय बाजार में कास्टिक सोडे के पाटन के तरीके को अपनाया है।

(vi) इंडोनेशिया, ताइवान, बैल्जियम और इटली में उत्पादकों भारत में वस्तुओं के पाटन में शामिल हैं। इन देशों से सीधे ही आपूर्तियों योजित की जाती हैं। बैल्जियम और इटली यूरोपीय संघ के देश हैं। यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों में कास्टिक सोडा के कई उत्पादक हैं। यूरोपीय संघ और विभिन्न सदस्य देशों में कोई कस्टम बाउन्डरीज नहीं है। पूरे यूरोपीय संघ में मूल्य एक जैसे ही होने की आशा की जा सकती है। सारे यूरोपीय संघ पर शुल्क लगाये बिना पाटन रोधी शुल्क लगाया जाना प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि इटली और बैल्जियम पर पाटन रोधी

शुल्क लगाने के पश्चात अन्य स्रोतों से पाटन की शुरुआत हो सकती है। वास्तव में, यूरोपीय संघ के एक देश अर्थात् फ्रांस पर पाटन रोधी शुल्क लगाये जाने के बाद इटली और बैल्जियम से निर्यातकों ने पाटित मूल्यों पर भारतीय बाजार में कास्टिक सोडे का निर्यात किया है। अतः याचिकाकर्ता नामित प्राधिकारी से यूरोपीय संघ पर जांच शुरू करने का अनुरोध करते हैं। तथापि, चूंकि फ्रांस पहले ही मौजूदा उपायों के तहत आता है अतः जांच को फ्रांस को छोड़कर यूरोपीय संघ पर सीमित किया जा सकता है।

ख. घरेलू उद्योग

यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स अल्काली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (ए0एम0ए0आई0) द्वारा दायर की गई है और जो मैसर्स डी0सी0 डब्ल्यू लिमिटेड, मुम्बई, मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि0, नागदा, मध्यप्रदेश, मैसर्स बिहार कैमिकल्स कम्पलेक्स, पटियाला, पंजाब मैसर्स जयश्री कैमिकल्स लिमि0, उड़ीसा; मैसर्स आंध्रा शुगर लिमि, तंबाकू, डी0सी0एम0 श्री राम, नई दिल्ली। मैसर्स इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि0, बडोदरा, मैसर्स स्टैंडर्ड अल्काली, मुम्बई और मैसर्स डी0सी0एम0 श्री राम कन्सोलिडेटेड लि0, नई दिल्ली द्वारा समर्थित है। संबद्ध वस्तु के उत्पादन में याचिकाकर्ता कंपनियों की हिस्सेदारी 55.67 प्रतिशत है और इस प्रकार उनका घरेलू उद्योग की ओर से यह याचिका दायर करने का हक बनता है।

(i) डी0सी0डब्ल्यू0 लिमि0 एक बहु उत्पाद कंपनी है जो विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में लगी हुई है जैसे कि सोडा एश, कास्टिक सोडा के लिये ठोस और नमकीन फ्लैक्स कैल्शियम क्लोराइड, सोडा वाइकारबोनेट, एल्युमिनम बाईकारबोनेट, नमक आदि।

(ii) गुजराज अल्काली एंड कैमिकल्स लिमि0 भी एक बहु उत्पाद कंपनी है जो व्यापक प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रही है जिसमें कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस सोडियम साइनाइट, हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम फैरोसाइनाइट, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोआक्साइड, पोटेशियम कारबोनेट, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन पैराआक्साइट आदि।

(iii) सर्व कैमिकल्स; यूनाइटेड फास्फोरस लिमि० की एक सहायक कम्पनी है । एस०सी० आई०एल० एक बहु उत्पादी कम्पनी है जो विभिन्न रसायनों के उत्पादन में लगी हुई है जैसे कि यलो फास्फोरस , आइसो प्रोपाइल बोमाइड, थियोदी फीनोल, मिथाइलिन ग्लोटेरोनीराइट, ऐसीटल बोमाइड, पैरा नाइट्रो बैन्जाइल एल्कोहल और ट्रीफिनाइल फास्फोरस थोयोनेट आदि । यह कम्पनी विद्युत अथवा बिजली के उत्पादन में भी लगी हुई है ।

(iv) ग्रासिम उद्योग लिमि०, आदित्य बिरला ग्रुप की एक मुख्य कम्पनी है । ग्रासिम उद्योग लिमिटेड एक बहु-उत्पादी, बहु-स्थानीय और अच्छी प्रकार से विविधीकृत कम्पनी है जोकि विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में लगी हुई है जैसे कि विस्कोज स्टेपल फाइबर, वाइट सीमेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डोमेस्टिक इण्डस्ट्रीज सल्फेट, रेयान ग्रेड पल्प, पेपर, स्टेबल ब्लीचिंग पावडर, मैन-मेड फाइबर फैब्रिक्स, मैन-मेड फाइबर यार्न, ग्रे सीमेंट, आर्टिकल्स ऑफ सीमेंट कांक्रीट, इण्डस्ट्रीयल मशीनरी, पोली एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरो सल्फोनिक एसिड, और स्पॉन्ज आइरन, आदि ।

(v) आंध्रा शुगर लिमिटेड एक बहुत-उत्पादी, बहु-स्थानिक कम्पनी है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने में लगी हुई है जैसे कि शुगर, ऐसेटिक एसिड, इण्डस्ट्रीयल एल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, सुपरफास्फेट, क्लोरोसलफोनिक एसिड, ओलियम, एसप्रिन, कार्बन डाइआक्साइड, एलुम डिफ्यूजर्स, केमिकल इक्वुपमेंट, शुगर फैक्टरी बायलिंग हाउस इक्वुपमेंट्स, अनसाइमेट्रीकल डिमीथल हाइड्राजिन, कॉटन सीड्स आदि ; रिचबर्न और आएल केक्स प्रोसेसिंग, रिफाइनरी, हाइड्रोजिनेशन आफ आयल्स कैटल और पोलट्री फीड, विंड पावर विद्युत आदि ।

(vi) बिहार कास्टिक, जयश्री केमिकल्स और एस०आई०एल० (रसायनिक परिसर) केवल कास्टिक सोडा और इसके उप-उत्पादों के उत्पादन में लगे हुए हैं ।

(vii) मैसर्स आई०पी०सी०एल०एफ० एक बहु-उत्पादी कम्पनी है और इसके उत्पादों में यह उत्पाद शामिल हैं - जैसे एथिलीन, प्रोपीलीन, बूटाडीन, ब्यूटीन-1, बैन्जीन, सिक्सोन, कार्बन ब्लैक फीडस्टाक, एक्रीलोनीट्रिलिक, इन्डोथीन, इन्डोथीन-एल०एल०/इन्डोथीन एच०डी०, कोइलीन,

कोइलीन-सी०पी०, कोइलीन ए०डी०एल०, इन्डोविन, सीसेमर, इथाइलिन आक्साइड, इथइलिन ग्लाइकोल, इन्डाक्रील, सूपाक्रील, एक्रीलेट्स, पैट्रेज, लीनियर एल्काइल बेन्जीन, पैरा एकजलीन, आर्थो एकजीलीन, स्मेल्वेंज सी०आई०एक्स०, हैप्टोन, डेमीथइल टेरीपिथलेट, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, पावर (एम०डब्ल्यू०एच०)

ग. समान प्रकार की वस्तु

(i) भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन और कोरिया से आयातित कास्टिक सोडे में कोई अन्तर नहीं है। साधारणतया, भारतीय उद्योग और विशेषतया भागीदार कम्पनियों द्वारा उत्पादित सोडा, विशेषताओं जैसे कि भौतिक, रसायनिक विशेषताओं, कच्ची सामग्री संघटक, कार्यों व उपयोग उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तु के शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप में प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ताओं ने दोनों का अदल-बदल कर उपयोग किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कास्टिक सोडे को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के तहत संबद्ध देशों से आयातित कास्टिक सोडे के लिए समान प्रकार की वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए।

(ii) जैसा कि इस याचिका में पहले उल्लेख किया गया है कि विश्व भर में तीन प्रक्रियाओं द्वारा कास्टिक सोडे का उत्पादन किया जा रहा है। भारतीय उद्योग भी इन सभी तीन प्रक्रियाओं को उपयोग में लाते हुए कास्टिक सोडे का उत्पादन कर रहा है। तथापि, प्रक्रिया में अन्तर का तात्पर्य इस का भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशों, विपणन, मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता दृष्टिकोण, शुल्क वर्गीकरण आदि के संदर्भ में उत्पाद में भिन्नता का होना नहीं है।

घ. पाटन

(i) चाइनीज ताइपेइ, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) से उत्पादक भारत में इस वस्तु के पाटन में लगे हुए हैं। यह पाटन मुख्यतया तीसरे देशों में व्यापारियों के माध्यम से किया जा रहा है। तथापि, इन देशों से आपूर्तियां सीधे ही योजित की जाती है।

(ii) कार्बोनाट सोडा एक मूल अकार्बनिक रसायन है और इसे कच्चे माल के रूप में कई उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है। इसका व्यापार मुख्यतया थोक मात्रा में किया जाता है और अतः खेप सामान्यतया सीधे ही मूल देश से होती है। तथापि, मौजूदा मामले और विशेषकर एक बहुत बड़ी मात्रा में क्रय के लिए नालको द्वारा दी गई निविदा में तीसरे देश में स्थित व्यापारियों ने भाग लिया है जिनमें सीधे ही संबद्ध देशों से आपूर्तियां की जानी होती है।

(iii) हाल ही में नालकों ने 115000 मीटरी टन कार्बोनाट सोडा के लिए निविदा दी है। नालको द्वारा दी गई निविदा में कई निर्यातकों ने भाग लिया है। दी गई निविदा की मात्रा काफी अधिक है।

(iv) संबद्ध देशों और अन्य देशों जिनके विरुद्ध जांच प्रगति पर है अथवा जो देश अब शुल्क आकृष्ट कर रहे हैं, से निर्यातकों ने इस निविदा में भाग लिया है। दी गई निविदा का ब्यौरा, निर्यातक का नाम, एजेंट का नाम, प्रस्तावित मात्रा, प्रस्तावित मूल्य, प्रस्तावित संशोधित मूल्य, पर कामित मूल्य जिस पर नालको द्वारा आर्डर दिया गया है, आयतित सामग्री का पंधुच मूल्य आदि का ब्यौरा "निविदा विवरण" में दिया गया है।

(v) हाल ही में एक प्रमुख उपयोगकर्ता मैसर्स नालको ने 115000 मीटरी टन कार्बोनाट सोडा के लिए विश्व भर में एक निविदा दी है।

"आर्डर दिये जाने के बाद भारत सरकार द्वारा पाटन रोधी शुल्क लगाने के दशा में आपूर्तिकर्ता उसी मूल्य पर और आर्डर की शर्तों पर अन्य गैर पाटन रोधी स्रोत से आपूर्ति प्राप्त करने के लिए सभी प्रयत्न करेगा। भारत सरकार द्वारा पाटन रोधी शुल्क लगाने की तिथि से गैर-पाटन रोधी स्रोतों से सामग्री का प्रबन्ध करने के लिए क्रेता द्वारा अनुमत समय, तीस दिन होगा। तथापि, यदि विक्रेता उपर्युक्त के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहता है तो क्रेता को यह अधिकार है कि वह किसी भी पक्ष पर वित्तीय देयता के वगैर निविदा की शेष मात्रा के लिए आर्डर को समाप्त कर दे। इस में वह शिपमेन्ट शामिल नहीं होगा जो कि पारगमन में है।"

(vi) इण्डोनेशिया, ताइवान और यूरोपीय संघ से निर्यातक और उत्पादक भारतीय बाजार में कार्बोनाट सोडा का पाटन कर रहे हैं। यह घरेलू उद्योग की बाजार सूचना है कि काफी सामग्री

भारत में विभिन्न कस्टम पत्तनों पर शीघ्र ही उतारी जाने वाली है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि घरेलू उद्योग ने पहले भी दो बार इण्डोनेशिया पर अन्य बातों के साथ-साथ पाटन रोधी शुल्क लगाने के लिए एक याचिका दी थी। तथापि, इण्डोनेशिया के विरुद्ध जांच शुरू नहीं की गई थी। स्थिति से लाभ लेकर अर्थात् कुछ अन्य देशों के विरुद्ध पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से और इण्डोनेशिया से होने वाले आयातों पर कोई शुल्क न लगाए जाने से इण्डोनेशिया से उत्पादकों और निर्यातकों ने अब इसे एक अच्छा अवसर पाया कि विभिन्न देशों से निर्यात मूल्य में आई भारी कमी के समय वे सामग्री को पाट सकें।

(vii) यह देखा जा सकता है कि नालको ने 115000 मीटरी टन के लिए आदेश दिया है जो भारत में किसी एक वर्ष में कास्टिक सोडा के कुल आयात से अधिक है।

(viii) उन मूल्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं जिन मूल्यों पर निर्यातकों द्वारा अपने घरेलू बाजार में कास्टिक सोडा का विक्रय किया जा रहा है। हम एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका से विशेषतौर पर बैल्जियम के घरेलू बाजार में और सामान्यतौर पर यूरोपीय संघ में मूल्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इस संबंध में "क्लोर अल्काली" में प्रकाशित सूचना पर भरोसा रखा जा रहा है। क्लोर-अल्काली पत्रिका नियमित तौर पर यूरोपीय संघ में घरेलू बाजार में कास्टिक सोडा के मूल्यों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट देती है। इस प्रकार क्लोर अल्काली पत्रिका में दिए गए मूल्यों पर विचार करते हुए निर्यातक देश में सामान्य मूल्य की गणना की गई है।

(ix) उन मूल्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं जिन मूल्यों पर इण्डोनेशिया और ताइवान से निर्यातकों द्वारा उनके घरेलू बाजार में कास्टिक सोडा की बिक्री की जा रही है। याचिकाकर्ता एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका से इण्डोनेशिया और ताइवान के घरेलू बाजार में मूल्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इस संबंध में क्लोर अल्काली पत्रिका में प्रकाशित सूचना पर भरोसा रखा जा रहा है। क्लोर-अल्काली पत्रिका इण्डोनेशिया और ताइवान में घरेलू बाजार में कास्टिक सोडा के मूल्यों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट देती है इस प्रकार, क्लोर अल्काली में दिए गए मूल्यों पर विचार करते हुए इन देशों में सामान्य मूल्य की गणना की गई है।

(x) भारतीय बाजार में कास्टिक सोडा के भारी पाटन से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है । इसके अलावा, नाल्कों द्वारा दिया गया आर्डर, घरेलू उद्योग को और अधिक भौतिक क्षति पहुंचाएगा जैसा कि क्षति साक्ष्य के बारे में दिए गए पैराग्राफ में देखा जा सकता है ।

ड. क्षति

(i) क्षति की घमकी के बारे में नियम इस बात का उल्लेख करता है कि भौतिक क्षति की घमकी में निर्धारण को तथ्यों पर आधारित किया जाएगा न कि केवल आरोप, अनुमान और दूर की संभावनाओं पर । परिस्थितियों में बदलाव को, जो कि एक ऐसी स्थिति सृजित करती हो जिसमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए । क्षति की घमकी का निर्धारण करने में प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार के तथ्यों और निम्न को ध्यान में रखेंगे:-

(क) भारत में पाटित आयातों में बहुत वृद्धि जो काफी बड़े हुए आयात की संभावनाओं को दर्शाती हो ;

(ख) किसी अतिरिक्त निर्यात को समा लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में काफी बड़े हुए आयातों की संभावनाओं को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में काफी वृद्धि ।

(ग) क्या आयात उन मूल्यों पर होने जा रहे हैं जो घरेलू मूल्यों पर काफी निराशाजनक और दवावकारी प्रभाव डालेंगे और जिससे और आयात किए जाने के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी ; और

(घ) वस्तु की सामान सूची की जांच की जा रही है ।

(ii) ऐसा समझा गया है कि अपने-अपने बाजार में संबद्ध देशों में उत्पादकों की क्षमता घरेलू मांग से काफी अधिक है । नालको को प्रस्ताव की गई सामग्री की यह बड़ी मात्रा इस बात का स्पष्ट

प्रमाण है कि उत्पादकों पर भारी दबाव है कि वे अपने सामान को बेचें । भारतीय उत्पादकों की कीमत पर निर्यातकों के लिए वृहत भारतीय बाजार स्वाभाविकतौर पर काफी लाभप्रद है ।

(iii) ऐसा समझा गया है कि निर्यातकों ने अपने भारतीय एजेंटों के माध्यम से काफी मात्रा के लिए आदेश दिए हैं, वास्तव में, नालको द्वारा 115000 मीटरी टन के लिए दिया गया आदेश (जिसके लिए निविदा पहले ही दी गई थी) अपने आप में भारत में कास्टिक सोडे के वार्षिक औसत आयात से अधिक है और इसकी क्षमता भी भारत में कई अलग-अलग उत्पादनों से अधिक है,

(iv) हमारी बाजार आसूचना दर्शाती है कि पाटन की काफी सामग्री पारगमन में है और शिपमेन्ट के यहां शीघ्र की पहुंचने की प्रत्याशा है । यदि आर्डर देने का मौजूदा क्रम जारी रहता है तो घरेलू उद्योग को बिक्री की काफी हानि होगी ।

(v) आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्यों से काफी नीचे है । उस सामग्री की मात्रा, जिसके लिए आर्डर दिए गए हैं, भारत में संबद्ध उत्पाद की मांग के संदर्भ में काफी अधिक है । इसके अलावा, यह बात देखी जानी चाहिए कि यदि संबद्ध देशों में उत्पादक, भारतीय बाजार में मौजूदा मूल्य पर अपनी सामग्री बेचते रहे तो घरेलू उद्योग, मौजूदा मूल्यों पर भी अपनी स्थिति नहीं बनाए रख सकेगा ।

(vi) आयातों का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग के उत्पादन की पूरी लागत और उचित बिक्री मूल्य से काफी कम है, घरेलू उद्योग को नकदी की हानि होगी यदि इसे समान मूल्यों पर बिक्री करनी पड़े । नालको द्वारा दिए गए आर्डर ने बाजार में मूल्य में भारी दबावकारी प्रभाव डाला है और यह अधिकतर प्रस्तावित जांच अवधि के बाद हुआ है ।

(vii) पाटन मार्जिन बहुत ही अधिक है। उन मूल्यों पर, जिन पर सामग्री का निर्यात किया जा रहा है, यहां तक कि उत्पादन की लागत भी वसूल नहीं हो पाती, बड़े निवेशों पर लाभ लेने की बात तो अलग रही ।

(viii) मौजूदा मामले में-

(क) पाटन का एक इतिहास है। पहले, घरेलू उद्योग को साऊदी अरब, यू.एस.ए., जापान, ईरान और फ्रांस से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा भारत में पाटन किए जाने के कारण क्षति हुई है, घरेलू उद्योग ने नामित प्राधिकारी से पाटन रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक विस्तृत जांच के उपरान्त पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की, जिसे तब से केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया गया है। इन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के पश्चात कतार ने भारत में कास्टिक सोडे का पाटन करना शुरू कर दिया। घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से कतार पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया। प्राथमिक जांचों के उपरान्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनन्तिम शुल्क लगाने की सिफारिश की। कतार के विरुद्ध जांच शुरू करने के पश्चात संबद्ध देशों से उत्पादकों और निर्यातकों ने इस सामग्री का पाटन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार, अब तक भारत में कास्टिक सोडे के पाटन का एक स्पष्ट इतिहास है।

(ख) आयातकों को यह स्पष्टतौर पर मालूम है कि वह मूल्य जिस पर संबद्ध देशों से निर्यात किया जा रहा है वह एक पाटन मूल्य है क्योंकि यह मूल्य उस संदर्भ मूल्य से काफी कम है जो मूल्य नामित प्राधिकारी द्वारा पिछली जांच द्वारा निर्धारित किया गया था। स्पष्टतया, आयतक और उपभोक्ता इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि सामग्री, पाटित मूल्यों पर आयतित की जा रही है।

(ग) एक अल्पावधि में संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा क्षति की जा रही है। साऊदी अरब, यू.एस.ए., जापान, ईरान, फ्रांस और कतार पर शुल्क लगाए जाने के उपरान्त संबद्ध देशों में स्थित उत्पादकों ने पाटन करना शुरू कर दिया। हमारी बाजार आसूचना सुझाती है कि निर्यातक ने भारी आर्डर दिए हैं जो निर्यात के प्रक्रियाधीन हैं।

(घ) सालको द्वारा हाल ही में दी गई निविदा में एक ही आदेश में घरेलू उद्योग द्वारा लगभग 115000 मीटरी टन की मात्रा की बिक्री की हानि उठाई गई है क्योंकि इन स्रोतों से निर्यातकों द्वारा दिए (कोट किए) गए मूल्य, भारतीय उत्पादकों द्वारा दिए (कोट किए) गए मूल्यों से काफी कम हैं।

(ड.) प्राधिकारी को मुहैया कराई गई भाग लेने कम्पनियों की बिक्री की मात्रा दर्शाती है कि भाग लेने वाली कम्पनियों की मात्रा जो कमोवेश 2001 तक स्थिर थी उसमें वर्ष 2002 के पहले दो तिमाहियों में कमी आई है। इसके अलावा, भाग लेने कुछ कम्पनियों की बिक्री की मात्रा में नालकों द्वारा दी गई 115000 मीटरी टन की मौजूदा निविदा के कारण और कमी आई है।

(च) संबद्ध देशों से कास्टिक सोडे के आयात के अचानक वृद्धि हुई है। कभी-कभार के आयात की स्थिति से, केवल नालको द्वारा किए गए आयात की मात्रा, सभी देशों से होने वाले कुल आयात की मात्रा और देश में कई उत्पादकों की क्षमता से अधिक होगी। इसके अलावा, आयातों में हुई अचानक वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत में कास्टिक सोडे के आयातों ; और भारत में कास्टिक सोडे की मांग में आयातों के अंश में काफी वृद्धि हुई है।

(छ) भाग लेने वाली कम्पनियों का उत्पादन, जिसमें 2000-01 तक वृद्धि हो रही थी, में अप्रैल-दिसंबर 2001 में कमी आई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि केवल उत्पादन स्तर में परिवर्तन की बात घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को नहीं दर्शा पाएगी। वह मूल्य अधिक महत्वपूर्ण मापदण्ड हैं जिस पर संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा बिक्री का प्रस्ताव किया गया है और जिन मूल्यों पर घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों को ध्यान में रखते हुए बिक्री करनी पड़ी है अथवा बिक्री करनी पड़ सकती है।

(ज) कास्टिक सोडे के उद्योग ने देश में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया है। इस उद्योग में गिरावट आने से रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(झ) याचिकाकर्ताओं को पाटित आयातों के कारण काफी हानि हुई है। नालको द्वारा दिए गए आर्डर की हानि घरेलू उद्योग के लिए बिक्री की एक बड़ी हानि है।

(ञ) भागीदारी करने वाली कम्पनियों को लाभ हुआ है और घरेलू उद्योग को भारी हानियां हो रही है।

(ट) अन्य देशों से कास्टिक सोडे का आयात (सिवाए उन देशों को छोड़कर जिन पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है अथवा सिवाए उन देशों को छोड़कर जिनके बारे में जांच चल रही है) काफी कम है अथवा उन मूल्यों पर है जिससे भारतीय उद्योग को कोई हानि नहीं हो रही है।

(ठ) संबद्ध देशों से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है। जैसा कि याचिका में पहले भी उल्लेख किया गया है, कि घरेलू उद्योग पिछले कई वर्षों से कास्टिक सोडे का उत्पादन कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी निर्यातकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है। विनिर्माण करने की प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अन्य देशों में (जिन पर पहले ही शुल्क लगा हुआ है अथवा जिनके प्रति जांच चल रही है) से पाटित आयातों के साथ-साथ संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा मूल्यों में कमी किया जाना घरेलू उद्योग को होने वाली मौजूदा क्षति के लिए प्रमुख कारण है।

(ड) उन देशों को छोड़कर जहां पहले ही पाटन रोधी शुल्क लगा हुआ है, संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों से होने वाला कास्टिक सोडा का आयात लगभग नगण्य व बहुत ही कम है और यह घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है।

मांग की कमी के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

2. आयातकों के विचार

मैसर्स नालको, भुवनेश्वर ने आयातकों की प्रश्नावली में अधिसूचना के प्रति उत्तर भेजा था लेकिन इसमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध आदि का ब्यौरा नहीं दिया गया था। मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने भी आयातक प्रश्नावली में अधिसूचना के प्रति उत्तर दिया था लेकिन इसमें भी पाटन क्षति और कारणात्मक संबंध आदि के प्रति कोई तक नहीं दिए गए थे।

मैसर्स हिन्द लीवर लिमिटेड, मुंबई ने आयातकों की प्रश्नावली में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की लेकिन इसमें भी पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध आदि का ब्यौरा नहीं दिया गया है।

3. निर्यातकों के विचार

मैसर्स सोलवे बुशेल्स, बेल्जियम ने अधिसूचना के प्रति उत्तर दिया लेकिन यह सूचना निर्यातकों की प्रश्नावली में नहीं दी गई है और केवल चार पृष्ठों में अगोपनीय ब्योरा दिया है जो अन्यथा अपूर्ण है।

मैसर्स बी.ए.एस.एफ. एन्टवरपन एन.वी.(बैल्जियम) ने शुरू में निर्यातकों की प्रश्नावली दायर करने के लिए समय में छूट देने का अनुरोध किया था और प्राधिकारी ने उनके अनुरोध पर उचित रूप से विचार करके उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उन्हें 10 दिसम्बर, 2002 तक निर्यातक प्रश्नावली दायर करने का समय विस्तार दिया, परन्तु दिनांक 7 नवम्बर, 2002 के पत्र द्वारा उन्होंने जांच अवधि के दौरान अथवा इससे पहले भारत में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में जांचाधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

मैसर्स बी.ए.एस.एफ. ए.जी. लुडबिगशाफेन (जर्मनी) सूचित किया है कि उन्होंने भारत में जांच के दौरान अथवा इससे पूर्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में जांचाधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

मैसर्स बेयर शैल आइसोसाइनेट्स एन.वी ने बताया है कि उन्होंने भारत में जांच के दौरान अथवा इससे पूर्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जांचाधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

(ग) प्राधिकारी द्वारा जांच और निकाले गये निष्कर्ष:

इन निष्कर्षों पर पहुंचते समय आयातकों, निर्यातकों, उपयोगकर्ताओं, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई और उन पर विचार किया गया और जहां कहीं भी उचित समझा गया उन पर इसके बाद विचार किया गया।

उन नये निर्यातकों के मामले में, जो मूल्यों कि अन्डरटेकिंग देने के लिए इच्छुक कहे गये हैं, अनुरोध किये जाने पर उपरोक्त नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

कुछ निर्यातकों और विनिर्माताओं ने दावा किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया है। यह प्रथा रही है कि इन निर्यातकों को जब भी वह भारत को

निर्यात करें उपर्युक्त पाटन रोधी नियमों के नियम 22 के तहत नये निर्यातकों के रूप में पुनरीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए।

1. विचाराधीन उत्पाद:

चाइनीज ताइपे, इन्डोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के मूल का अथवा वहां से निर्यातित मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्लसाइड (एन.ए.ओ.एच.) जिसे साधारणतया कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है।

कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक, झाग वाला बहुत ही क्षारीय और गंधहीन रसायन है और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पल्प और पेपर, न्यूजप्रिंट, बिस्कोज यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्यूमिनियम काटन, टेक्सटाइल्स, टाइलट और लांड्री सोपस, डिटरजेंट, डाई स्टाफ, ड्रग्स और औषधि बनाने, पेट्रोलियम शुद्धिकरण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा, कस्टम शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के तहत कस्टम टैरीफ एक्ट, 1975 के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत है। आई.टी.सी. के 8 डिजिट के वर्गीकरण के अनुसार इस उत्पाद को कस्टम शीर्ष 2815.1101, 2815.1102 और 2815.1200, के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, मौजूदा वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह मौजूदा जांच की परिधि पर बाध्यकारी नहीं है।

कास्टिक सोडा का दो प्रकारों में अर्थात् तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं द्वारा अर्थात् मरक्युरी शैल प्रोसेस, डाइअफ्रैम प्रोसेस और मेमबरेन प्रोसेस द्वारा सज्जीदार पानी (ली) और ठोस (सोलिड) रूप में उत्पादित किया जाता है। कास्टिक सोडा को ओ0जी0एल0 के तहत आयातित किया जा सकता है यह 30% का मूल सीमा शुल्क आकृष्ट करता है। मौजूदा जांच में कास्टिक सोडे के सभी रूप शामिल हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में कास्टिक सोडा के (ली) और फ्लैक्स दोनों के सभी प्रकार शामिल हैं और इसी प्रकार की संबद्ध वस्तु के सभी विभिन्न प्रकार, उपयोगकर्ताओं की मांग के आधार पर प्रतिस्थापनीय रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अतः विभिन्न सांद्रताओं में ये दोनों प्रकार, जांच की विषय वस्तु हैं। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए केवल डी0एम0टी0 आधार पर उचित तुलना की है।

2. समान प्रकार वस्तु

प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन के द्वारा उत्पादित वस्तु, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं के लिए समान प्रकार की वस्तु जैसी ही है। इसके अलावा, ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और उपभोक्ता, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आयातित वस्तु को अदल-बदल कर उपयोग में ला रहे हैं। यह उल्लेख किया गया है कि कास्टिक सोडा विश्वभर में तीन प्रक्रियाओं अर्थात् मरक्युरी सेल प्रोसेस, डाइअफ्रैम प्रोसेस और मेमब्रेन प्रोसेस द्वारा संसाधित किया जा रहा है। इन प्रक्रियाओं में अन्तर होने का तात्पर्य उत्पाद में अन्तर होना नहीं है। इसके अलावा, इन तीन प्रक्रियाओं (प्रोसेस) के कारण उत्पादन की लागत में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु, और संबद्ध देशों से निर्यात की जा रही वस्तु नियमों की परिभाषा के भीतर समान प्रकार की वस्तु है।

अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गये तर्कों और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की प्रतिस्थापनीयता और अदला-बदली की प्रयोजनीयता को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य के लिए नियम 2(घ) के अनुसार निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को समान प्रकार की वस्तु मानते हैं।

3. घरेलू उद्योग

घरेलू उद्योग की ओर यह याचिका मैसर्स अल्काली मैनुफैक्चरर्स एसोशियेशन आफ इंडिया, दिल्ली की ओर से दायर की गई है। यह संघ, भारत में कास्टिक सोडे के सभी घरेलू विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह याचिका इन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है अर्थात् मैसर्स डी0सी0डब्ल्यू0 लिमिटेड, मुंबई, मैसर्स गुजरात अल्कालीज एंड कैमिकल्स लि0, बड़ौदा, मैसर्स सर्च कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि0, मुम्बई, मैसर्स ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0, नागदा (मध्यप्रदेश), मैसर्स एस0आई0ई0एल0 कैमिकल कमप्लैक्स, पंजाब, मैसर्स बिहार कास्टिक एण्ड कैमिकल्स लि0 झारखंड, मैसर्स जयश्री कैमिकल्स लि0, उडीसा और मैसर्स आंध्रा शुगर लि0, तनाकू उत्पादनाधीन

संबद्ध वस्तु में इन याचिकाकर्ता कम्पनियों की भागीदारी 49.09% है और मैसर्स इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कांफरिशन लि० बड़ोदा, मैसर्स स्टैंडर्ड अल्काली, मुंबई और मैसर्स डी०सी०एम० श्रीराम कन्सोलिडेटेड लि०, नई दिल्ली के साथ उनकी भागीदारी का प्रतिशत 55.67% है ।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उन घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने इस याचिका का समर्थन किया है, की भागीदारी कुल घरेलू उत्पादन के 50% से अधिक की है और अतः उनका पाटनरोधी नियम के नियम 5(3)(क) और (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का हक बनता है और वे नियम 2(ख) के संदर्भ में घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं ।

4. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

३ क(1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है कि:-

(i) सामान्य तौर पर होने वाले व्यापार में उस समान प्रकार के वस्तु के लिये तुलनात्मक मूल्य जो उपखंड (6) के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खपत के लिये अभिप्रेत हों ; और ।

(ii) जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य तौर पर होने वाले व्यापार में समान प्रकार की वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती हो अथवा जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में किसी विशेष प्रकार की बाजार स्थिति अथवा बिक्री की कम मात्रा के कारण इस प्रकार की बिक्री से एक उचित तुलना नहीं हो पाती तो सामान्य मूल्य निम्न में से कोई एक होगा:-

(क) उपनियम 6 के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार यथानिर्धारित समान प्रकार की उस वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधित्व मूल्य जब वह वस्तु निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा किसी उचित तीसरे देश से निर्यातित होती हो ; अथवा

(ख) प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और उपनियम 6 के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार यथानिर्धारित लाभ के लिये उचित मार्जिन के साथ मूल के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

बशर्ते कि मूल के देश से अन्य के उस देश से जहां यह वस्तु निर्यात के देश के माध्यम से केवल जहाज से भेजी गई हो अथवा इस प्रकार की वस्तु का निर्यात किये जाने वाले देश में उत्पादन नहीं किया जाता अथवा निर्यात किये जाने वाले देश में इसका कोई तुलनात्मक मूल्य न हो, वस्तु का आयात किये जाने की दशा में सामान्य मूल्य, उद्भव के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जायेगा ।

सामान्य मूल्य और एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य के निर्धारण का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर)

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी ने खंड 9 का (1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिये सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी । मै0 बी0ए0एस0एफ0, बैल्जियम, मै0 बी0ए0एस0एफ0, जर्मनी, मैसर्स बेयर शैल आइसोथानेट्स एन0 बी0, बैल्जियम ने उल्लेख किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया है । मैसर्स सोलवे, बैल्जियम ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली में ब्यौरा दिये बिना चार पृष्ठों का अपूर्ण उत्तर दायर किया है ।

यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) से निर्यातकों द्वारा दायर अपर्याप्त और अपूर्ण उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्ष के उद्देश्य के लिये घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया है व उस पर भरोशा किया है । तथापि, निर्यातक द्वारा दी गई सूचना की प्रश्नावली के अनुसार अपेक्षित पूरी सूचना दिये जाने के बाद ध्यान में रखा जायेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्थात् क्लोर अलकाली से द्वितीय स्रोतों के माध्यम से उनके घरेलू बाजार में याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये आंकड़ों के आधार पर सभी

उत्पादकों/निर्यातकों के लिये यूरोपीय संघ में (फ्रांस को छोड़कर) संबद्ध वस्तु के लिये उचित समायोजन के साथ सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है ।

प्राधिकारी ने इस प्रकार के उत्पादकों/निर्यातकों के लिये **** अमेरिकी डालर/डी0एम0टी0 का सामान्य मूल्य संदर्भित किया है ।

(ख) निर्यात मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा डीजीसीआई एंड एस से एकत्रित किये गये आंकड़ों के आधार पर उनके द्वारा निर्यात मूल्य दिया गया है । याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बन्दरगाह के व्ययों और अंतर्देशीय भाड़े के लिये क्रमशः ****अमेरिकी डालर/डीएमटी, ****अमेरिकी डालर/ डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी और **** अमेरिकी डालर/डीएमटी की सीमा तक समायोजनों का दावा भी किया है ।

एक्स फैक्टो निर्यात मूल्य **** अमेरिकी डालर/डीएमटी संदर्भित किया गया है ।

इन्डोनेशिया

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन्डोनेशिया से किसी भी निर्यातक ने प्रश्नवाली द्वारा उत्तर नहीं दिया है । प्राधिकारी ने इस असहयोग को ध्यान में रखते हुए निर्यातक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर इन्डोनेशिया के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्थात् क्लोर अलकाली के द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा उनके घरेलू बाजार में दिये गये आंकड़ों के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये इन्डोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के लिये समायोजन के साथ सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है ।

अतः अंतिम निर्धारण किये जाने तक प्रारम्भिक निर्धारण किये जाने के उद्देश्य के लिये इन्डोनेशिया के लिये सामान्य मूल्य ***** अमेरिकी डालर/डीएमटी संदर्भित की गई है ।

(ख) निर्यात मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा डीजीसीआई एंड एस से एकत्रित किये गये आंकड़ों के आधार पर उनके द्वारा निर्यात मूल्य दिया गया है । याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बन्दरगाह के व्ययों और अंतर्देशीय भाड़े के लिये क्रमशः *****अमेरिकी डालर/डीएमटी, ***** अमेरिकी डालर/डीएमटी, ***** अमेरिकी डालर/ डीएमटी, ***** अमेरिकी डालर/डीएमटी और ***** अमेरिकी डालर/डीएमटीकी सीमा तक समायोजनों का दावा भी किया है।

एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य ***** अमेरिकी डालर/डीएमटी संदर्भित किया गया है ।

चाइनीज ताइपे

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि चाइनीज ताइपे से किसी भी निर्यातक ने प्रश्नवाली द्वारा उत्तर नहीं दिया है । प्राधिकारी ने इस असहयोग को ध्यान में रखते हुए निर्यातक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर चाइनीज ताइपे के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्थात् क्लोर अलकाली के द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा उनके घरेले बाजार में दिये गये आंकड़ों के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये चाइनीज ताइपे में संबद्ध वस्तुओं के लिये समायोजन के साथ सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है ।

अतः अंतिम निर्धारण किये जाने तक प्रारम्भिक निर्धारण किये जाने के उद्देश्य के लिये चाइनीज ताइपे के लिये सामान्य मूल्य ***** अमेरिकी डालर/डीएमटी संदर्भित किया गया है ।

(ख) निर्यात मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा द्वितीयक से एकत्रित किये गये आंकड़ों के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्यात मूल्य दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा और बन्दरगाह के व्ययों के लिये क्रमशः ****अमेरिकी डालर/डीएमटी, ****अमेरिकी डालर/डीएमटी, ****अमेरिकी डालर/डीएमटी, ****अमेरिकी डालर/डीएमटी और **** अमेरिकी डालर/डीएमटी की सीमा तक समायोजनों का दावा भी किया है।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जनवरी जुलाई 2002 की अवधि के लिए डी जी सी आई एण्ड एस से प्राप्त कारोबार -बार आंकड़े, ताइवान से किसी भी आयात को नहीं दर्शा रहे हैं, जबकि मैसर्स नालको जो कि एक सहयोग करने वाला आयातक है, ने अप्रैल 2002 तक चाइनीज ताइपे से 26189 मीटरी टन की सीमा तक आयात दर्शाये हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया वह साक्ष्य, जो प्रस्ताव को निर्दिष्ट करता है जांचावधि में भारत में आयतकों द्वारा भी किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मैसर्स नालको ने 8 जुलाई, 2000 को निविदा दी थी और मूल्य की बोली 13 अगस्त, 2002 को खोली गई थी और कास्टिक सोडा की आपूर्ति के लिए ताइवान मूल के दो विदेशी पक्षों को आर्डर दिए गए थे। 151 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन की दर पर मैसर्स निशो हवाई को 30000 मीटरी टन और 174 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन की दर पर मैसर्स अंगल्फ पालीमर्स एण्ड केमिकल्स को 56000 मीटरी टन के लिए आर्डर दिए गए थे। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री की तिथि ; संविदा, क्रय आदेश, आदेश पुष्टिकरण अथवा बीजक की वह कोई भी तिथि हो सकती है। जो कोई भी बिक्री की मेटेरियल टर्मों को स्थापित करती हो। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना और उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने भारत को किए गए शिपमेंट से संबंधित निर्यात मूल्य को ****अमेरिकी डालर/डी.एम.टी., निर्दिष्ट किया है। याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बन्दरगाह के व्ययों और अंतर्देशीय भाड़े के लिये क्रमशः **** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/ डीएमटी, **** अमेरिकी

डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी और **** अमेरिकी डालर/डीएमटीकी सीमा तक समायोजनों का दावा भी किया है ।

एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य ****अमेरिकी डालर/डीएमटी संदर्भित किया गया है ।

5. पाटन - सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना:

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है:-

"पाटन के मार्जिन का निर्धारण करते समय नामित प्राधिकारी, निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना करेंगे । यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर और सामान्यतया एक्स-वर्क्स स्तर पर और जहां तक संभव हो लगभग उसी समय की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी । प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुण आधार पर उन अन्तरों के लिए उचित छूट दी जाएगी जिनसे बिक्री की शर्तों, कर प्रणाली, व्यापार के स्तरों, मात्रा, भौतिक विशेषताओं में अन्तरों और किन्हीं अन्य अन्तरों जो मूल्य की तुलनात्मकता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं सहित मूल्य की तुलनात्मकता प्रभावित होती हो ।

संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटनमार्जिन का मानांकन करने के लिए प्राधिकारी जांच की अवधि में भारित औसत एक्स-फैक्टरी निर्यात मूल्य के साथ सामान्य मूल्य की तुलना की है:-

निर्यातकों/आयातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्न प्रकार बैठता है:-

क्र० सं०	देश/निर्यातक/ उत्पादक	सामान्य मूल्य (डालर/एम.टी)	एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य (डालर/एम.टी)	ई.पी.के % के रूप में पाटन मार्जिन
1.	यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़ कर) सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	489.36%
2.	इण्डोनेशिया सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	299.87%
3.	चाइनीस ताईपे सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	58.79%

108GI/03-5

6. क्षति और कारणात्मक संबंध

उपर्युक्त नियम 11, अनुबंध-II के तहत जब क्षति का निष्कर्ष निकाला जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष निकालने में पाटित आयातों की मात्रा, समान प्रकार की वस्तु के लिए घरेलू बाजार में उनके मूल्यों पर प्रभाव और इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणात्मक प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण किया जाना शामिल होगा। चालू मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में इस बात की जांच की जानी आवश्यक है कि भारत में समान प्रकार की वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्यों में काफी कमी हुई है अथवा इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा मूल्यों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक कम करने अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है।

क्षति का सकल आकलन

रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह पाया गया है कि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन 2% की सीमा से अधिक था जिसे निर्यात मूल्य की प्रतिशतता में व्यक्त किया गया है। आयातों के प्रभाव का सकल आंकलन किया जाना उचित होगा क्योंकि संबद्ध देशों से किए जाने वाले निर्यात भारत में सीधे ही एक दूसरे से और भारत में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः प्राधिकारी, सकल तौर पर संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को आंकने का प्रस्ताव करते हैं।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए हम उपर्युक्त नियमों के अनुबंध II(iv) के अनुसार ऐसे अभिसूचकों पर विचार कर सकते हैं, जिसका उद्योग की स्थिति जैसे कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा आदि पर प्रभाव पड़ता हो।

क्षति की घमकी के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी नियम निम्न प्रकार से उल्लेख करते हैं-

भौतिक क्षति की घमकी के निर्धारण को तथ्यों पर आधारित किया जाएगा न कि केवल आरोप, अनुमान और दूर की संभावनाओं पर। परिस्थितियों में बदलाव को, जो कि एक ऐसी स्थिति सृजित करती हों जिसमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए। क्षति की घमकी का निर्धारण करने में प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार के तथ्यों और निम्न को ध्यान में रखेंगे:-

(क) भारत में पाटित आयातों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि जो काफी बढ़े हुए आयातों की संभावनाओं को दर्शाती हो ;

(ख) किसी अतिरिक्त निर्यात को समा लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में काफी बढ़े हुए आयातों की संभावनाओं को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में आई काफी वृद्धि को।

(ग) क्या आयात उन मूल्यों पर होने जा रहे हैं जो घरेलू मूल्यों पर काफी निराशाजनक और दवावकारी प्रभाव डालेंगे और जिससे और आयात किए जाने के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी ; और

(घ) वस्तु की सामान सूची की जांच की जा रही है।

भौतिक क्षति की घमकी के बारे में प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांचाधीन अवधि के दौरान पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अर्थात् 2001-2002 के दौरान 5472 की तुलना में 151614 मीटरी टन। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से ये आयात, घरेलू उद्योग के मूल्यों में काफी कमी करते हैं जिससे घरेलू उद्योग को अलाभकारी मूल्यों पर बिक्री करनी पड़ती है। इसके अलावा सामग्री एक ऐसे मूल्य पर आ रही है जो घरेलू मूल्य के बिक्री मूल्य से काफी कम है और यदि घरेलू उद्योग इस मूल्य पर बिक्री करना शुरू करता है तो इससे घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय हानि होगी। मैसर्स नालकों द्वारा संबद्ध देशों के हक में दिये गये आदेश से भी मात्रात्मक रूप से घरेलू उद्योग को काफी हानि होगी। सामान सूची में वृद्धि हुई है और यह

2000-2001 के 3371 मीटरी टन से बढ़कर 2001-2002 में 9133 हो गई है, जबकि जांच अवधि के दौरान इसमें सीमांतिक कमी आई है। अतः घरेलू उद्योग का संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण भौतिक हानि होने का जोखिम है।

उपर्युक्त बातों को नोट करने के पश्चात् प्राधिकारी यह विचार बनाते हैं कि संबद्ध उत्पादों से बिक्री की प्राप्ति पर उचित तौर पर विचार करके विभिन्न घरेलू उत्पादकों के लिये गैर क्षतिकारक मूल्य का आकलन किया गया है। इसके अलावा, अक्षमताओं को दूर करने में प्राधिकारी ने कच्चे माल, उपयोगी वस्तुओं आदि के उपयोग के बारे में सबसे अच्छी पद्धतियों को मापदंड बनाया है।

उस क्षति के बारे में जो भारत में उत्पादन के उच्चतर लागत के कारण हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी नियमों के तहत यह कमतर शुल्क नियम है जिसे लागू किया जाता है। इसके अलावा, पाटन रोधी शुल्क किसी भी दशा में पाटन मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता। अतः किसी भी दशा में यदि घरेलू उद्योग को ऐसी क्षति होती है जो पाटन मार्जिन से अधिक हो उसे निश्चयात्मक रूप से पाटन रोधी नियमों के तहत नहीं देखा जा सकता।

घरेलू उद्योग से संबंध आर्थिक मापदंडों की जांच करते समय पाटनरोधी शुल्क आकृष्ट करने वाले देशों और उन देशों जिनके बारे में जांच चल रही है, से पहले हुए पाटन द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

कास्टिक सोडे का पाटनरोधी मामले का इतिहास इस प्रकार से है:-

केस	देश
केस 1	संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, जापान, फ्रांस और साऊदी अरेबिया
केस 2	कतर
केस 3	कोरिया रिपब्लिक और चीन

प्राधिकारी उन घरेलू उत्पादकों के मामले में निम्नलिखित आर्थिक मापदंड नोट करते हैं व मानते हैं -

	1999-2000 (मीटरी टन)	2000-2001 (मीटरी टन)	2001-2002 (मीटरी टन)	जांचावधि (मीटरी टन)	वार्षिकीकृत (मीटरी टन)
आयात					
इंडोनेशिया	14860	0	4972	50546	67395
ताईवान	0	19033	327	85000	113333
यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़)	298	19964	173	20216	26955
संबद्ध देश	15157	38996	5472	155762	207683
आयात में बाजार आय					
संबद्ध देश (%)	17.47	52.97	13.97	70.50	70.50
घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड (मीटरी टन)					
क्षमता	809800	809800	822300	822300	822300
उत्पादन	728526	741555	740192	578000	770667
क्षमता उपयोग (%)	89.96	92	90.01	93.72	93.72
घरेलू बिक्री	519307	516048	522312	392248	522997
अंतर्देश स्टॉक	4347	3371	9133.3	8875.88	8876
उत्पादन की इकाई लागत (रु./मी. टन)	****	****	****	****	****
यूनिट बिक्री मूल्य(रु./मी. टन)	****	****	****	****	****
यूनिट लाभ/हानि (रु./मी. टन)	****	****	****	****	****
मांग	1391534	1409949	1406129	1193596	1591461.5
मांग में बाजार अंश (%)					
आयात	6.23	5.22	2.79	18.51	18.51
संबद्ध देश	1.09	2.77	0.39	13.05	13.05
अन्य देश	5.14	2.46	2.40	5.46	5.46
घरेलू उद्योग	37.32	36.60	37.15	32.86	32.86
भारतीय उद्योग	56.45	58.18	60.07	51.16	51.16
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयात (%)					
आयात	11.91	9.93	5.29	38.22	38.22
संबद्ध देश	2.08	5.26	0.74	26.95	26.95
अन्य देश	9.83	4.67	4.55	11.27	11.27

- (क) आयातों में निश्चित तौर पर वृद्धि हुई है ।
- (ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 1999-2000 पर जांचावधि में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि कई स्रोतों से पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है । तथापि, आयातों में वृद्धि की दर घरेलू उद्योग के उत्पादन की वृद्धि दर से काफी अधिक थी ।
- (ग) यद्यपि, घरेलू उद्योग , क्षमता उपयोग में वृद्धि करने में सफल रहे थे लेकिन इससे उद्योग को अपना लाभ बढ़ाने में मदद नहीं मिली, बल्कि लाभ में कमी आई ।
- (घ) नातकों द्वारा संबद्ध देशों को दिये गये आदेशों से घरेलू उद्योग को काफी मात्रात्मकता हांनि उठानी पड़ेगी ।
- (ङ.) उत्पादन और भारत में खपत के संबंध में आयातों में काफी वृद्धि हुई है ।
- (च) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यात मूल्य में काफी कमी आई है और यह 12914 रुपये प्रति मीटरी टन से घटकर 3800 रुपये मीटरी टन तक कम हुआ है ।
- (छ) कई देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद भी घरेलू उद्योग एक के बाद दूसरे देश से पाटन किए जाने के कारण लाभ लेने में समर्थ नहीं हो पाया है । वास्तव में, घरेलू उद्योग के लाभ में पिछले वर्षों में सुधार होने के बाद जांच की अवधि में कमी आई है ।
- (ज) पाटित आयातों के कारण भारतीय बाजार में मूल्यों में कमी आ रही, मूल्यों को कम करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में क्षरण हो रहा है ।
- (झ) कीमतों के गम्भीर रूप से कम होने के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को कीमतों में भारी कटौती करनी पड़ रही है ।
- (ञ) आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी नीचे था ।

(ट) वर्ष 2001-2002 के दौरान घरेलू उद्योग की समान सूची में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन जांचावधि के दौरान सीमांतिक कमी दृष्टिगत हुई है।

(ठ) घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के अलावा पाटित आयातों के कारण उन्हें और क्षति उठानी पड़ रही है।

(ड) घरेलू उद्योग उस मूल्य के बारे में चिंतित है जिस मूल्य पर उत्पाद का आयात किया जा रहा है। वह मूल्य एक पाटित मूल्य है जिस पर इस सामग्री का आयात किया जा रहा है। इसके अलावा, यह सामग्री, घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से काफी कम के मूल्यों पर बाजार में प्रविष्ट हो रही है। यदि, घरेलू उद्योग बराबर के मूल्यों पर बिक्री करना शुरू करता है तो इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियां उठानी पड़ सकती है।

(ढ) घरेलू उद्योग के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाए देश में मौजूदा विनियमों के अनुसार मजदूरी में वृद्धि करने के। तथापि, मजदूरी में वृद्धि करने से लाभ लेने की बात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि घरेलू उद्योग समानुपातिक रूप से मूल्यों में वृद्धि करने में समर्थ नहीं हो पाता है।

(ण) जांचावधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकदी लाभ में काफी कमी आई और इस प्रकार, इससे घरेलू उद्योग के रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ रहा है।

(च) यद्यपि, उत्पादकता में वृद्धि हुई है तथापि, इससे घरेलू उद्योग को अपनेलाभ को सुधारने में मदद नहीं मिली है, बल्कि लाभ में और गिरावट आई है।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि उद्योग को भौतिक क्षति हुई है।

7. भारतीय उद्योग का हित और अन्य विषय

प्राधिकारी यह भी विचार रखते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य साधारणतया पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षतियों को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली ओर उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्बहाली हो सके, जो बात देश के आम हित में है।

प्राधिकारी इस बात को भी मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु का उपयोग करने वाले विनिर्मित उत्पाद का मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणामस्वरूप यह

इन उत्पादनों की सम्बन्धात्मक प्रतिस्पर्धाओं पर कुछ असर डाल सकता है, तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा इन पाटनरोधी उपायों से कम नहीं हो पाएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय को लागू करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर किया जा सकेगा और इससे घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना, संबद्ध देशों से होने वाले आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा और अतः इससे उपभोक्ताओं के लिए इन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

8. पंहुच मूल्य

इस उद्देश्य के लिए आयातों का पंहुच मूल्य, निर्धारणीय मूल्य होगा जैसा कस्टम टेरिफ एक्ट 1962 के तहत कस्टम द्वारा निर्धारित किया जाए और सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा सिवाए कस्टम टेरिफ एक्ट, 1975 के खंड 3, 3क, 8 (ख), 9, 9 (क) के तहत लगाए गए शुल्क के।

(घ) निष्कर्ष:

पूर्वाक्त पर विचार करने के पश्चात यह देखा जाता है-

- (क) सभी रूपों में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी रूपों में संबद्ध वस्तु का भारत में इसके सामान्य मूल के कम में भारत में निर्यात किया गया है।
- (ख) घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति भी हुई है।
- (ग) इन आयातों से घरेलू उत्पाद के मूल्यों में कमी हुई जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को अलाभकारी मूल्यों पर बिक्री करनी पड़ रही है।
- (घ) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन द्वारा क्षति हुई है।
- (ङ) प्राधिकारी उन संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं जो संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित होती हैं और अध्याय 28 के तहत आती है।

(च.) ऐसा समझा गया कि पाटन के मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाए ताकि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके । तदनुसार, अध्याय 28, कस्टम टेरिफ के कस्टम उपशीर्ष 2815.11 और 2815.12 के तहत संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी संबद्ध वस्तुओं के आयात पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की तिथि से अंतिम निर्धारण किए जाने तक नीचे दी गई सारणी के कालम 3 में दी गई धन राशि और डालर/मीटरी टन में संबद्ध वस्तु के पहुंच के बीच के अन्तर के बराबर का अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ।

क्र.सं. 1.	देश/निर्यातक/उत्पादक 2.	धनराशि (अमेरिकी डालर/मी.टन) 3.
1.	यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़) सभी उत्पादक/निर्यातक	271.93
2.	इंडोनेशिया सभी उत्पादक/निर्यातक	233.58
3.	चाइनीज ताईपे सभी उत्पादक/निर्यातक	271.93

ड. आगे की प्रक्रिया:

प्रारम्भिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

(क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षों से इन निष्कर्षों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हैं, और अन्तिम निष्कर्षों में उन पर विचार किया जाएगा ।

(ख) संबंधित निर्यातकों/आयातकों, याचिकाकर्त्ताओं और संबंधित हितबद्ध पक्षों को अधिकारी द्वारा अलग से पत्र लिखे जा रहे हैं, जो पत्र के प्रेषण की तिथि से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं ।

(ग) प्राधिकारी यथा आवश्यक सीमा तक जांच करेंगे ।

(घ) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षों को मौखिक सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करेंगे जिसके लिए सभी हितबद्ध पक्षों को तिथि और समय से अवगत कराया जाएगा ।

(ड.) प्राधिकारी अंतिम निष्कर्षों की घोषणा किए जाने से पहले आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

एल. वी. सप्तर्षि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2003

Preliminary Findings

Sub: Anti-Dumping Investigation concerning imports of Caustic Soda from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France).

No.14/39/2002-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) (hereinafter referred to as petitioner) on behalf of the domestic industry, alleged dumping of Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France) (hereinafter referred to as subject countries). The petition was supported by M/s DCW Limited, Mumbai, M/s Gujarat Alkalis & Chemicals Limited, Vadodara, Gujarat, M/s Search Chem Industries Limited, Mumbai, M/s Grasim Industries Ltd, Nagda, M.P., M/s SIEL Chemical Complex, Patiala, Punjab, M/s Bihar Caustic & Chemicals, Ltd., Jharkhand, M/s Jayshree Chemicals Limited, Orissa, M/s Andhra Sugars Limited, Tanaku, DCM Sriram, New Delhi, M/S Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara, M/S Standard Alkali, Mumbai and M/S DCM Sriram Consolidated Ltd., New Delhi.
 - ii) Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioner revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was, therefore, considered as properly documented.
 - iii) The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner decided to initiate the investigation against imports of subject goods from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France). The authority notified the Embassies of Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France) in New Delhi about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with the sub-Rule 5(5) of the Rules.

- iv) The Authority issued a public notice dated 8th October 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under custom Code 281511 and 281512 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 (28151101, 28151102 and 28151200 of ITC) originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France)
- v) The Authority forwarded a copy of the public notice to the known exporters (whose details were made available by petitioner) and gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2):
- vi) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose details were made available by petitioner) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).
- vii) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.
- viii) The Authority provided a copy of the petition to the known exporters and the Embassy of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential petition was also provided to other interested parties, wherever requested.
- ix) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4):
 - 1. M/s. BASF Antwerpen. NV, Antwerpen, Belgium,
 - 2. M/s. Bayer Shell Isocyanates. NV, Antwerpen, Belgium,
 - 3. M/s. Solvay. S.A, Antwerpen, Belgium
 - 4. M/s. Asahimas Subentra Chemicals, Anyer, Indonesia
 - 5. M/s. Klani Kertas, East Kalimantan, Indonesia
 - 6. M/s. Musi Pulps Mill, Prabumulih South, Indonesia
 - 7. M/s. Ausimont, Bussi, Italy
 - 8. M/s. Enichem Spa, Assemini, Italy
 - 9. M/s. Cathay Chemicals Co. Ltd., Taiwan
 - 10. M/s. Cheng Tai Chemical Works, Chinese Taipei,
 - 11. M/s. Cheng Tong Chemicals Co., Chinese Taipei
- x) The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise all concerned exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the known exporters was also sent to the Embassy of the subject countries in accordance with Rule 6(3).
- xi) A questionnaire was sent to the following known importers/user associations of the subject goods in accordance with Rule 6(4):

1. M/s. Abhay Chemicals Ltd., Baroda
2. M/s. Albright Wilson Chemicals Ltd., Mumbai
3. M/s. Arvind Mills Ltd., Ahmedabad
4. M/s. Birla Cellulose Ltd., Bharuch
5. M/s. Central Pulp Mills Ltd., New Delhi
6. M/s. Deepak Nitrite Ltd., Nandesari
7. M/s. Godrej Soaps Ltd., Mumbai
8. M/s. Gujarat Electricity Board, Vadodara
9. M/s. Gujarat Narmade Fertilizers Co. Ltd., Bharuch
10. M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., Vadodara
11. M/s. Hindustan Lever Ltd., Mumbai
12. M/s. ICI India Ltd., Valsad
13. M/s. Indian Farmer Fertilizer Co.Op Ltd., Ghandinagar
14. M/s. Indian Oil Corporation Ltd., Vadodara
15. M/s. Indian Petrochemical Corporation Ltd., Vadodara
16. M/s. Jaysynth Dyechemical Ltd., Mumbai
17. M/s. Link Pharma Ltd., Baroda
18. M/s. Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad
19. M/s. Narmada Chematur Petrochemical Ltd., Bharuch
20. M/s. Nirma Limited, Ahmedabad
21. M/s. Pab Chemicals (P) Ltd., Baroda
22. M/s. Rama News Prints & Papers Ltd., Surat
23. M/s. Rubamin Limited, Baroda
24. M/s. Sabero Organics Ltd., Mumbai
25. M/s. Torrent Gujarat Bio-Tech Ltd., Baroda
26. M/s. Transpek Industries Ltd., Vadodara
27. M/s. National Aluminium Company Ltd., Bhubaneshwar
28. M/s. Cyanides & Chemicals Company, Mumbai
29. M/s. Demosha Chemicals Ltd., Mumbai
30. M/s. Transpek Silox Industry Ltd., Baoda
31. M/s. Deepak Nitrite Ltd., Pune
32. M/s. Hitsu Industries Ltd., Gujarat
33. M/s. Adani Exports Ltd., Ahmedabad
34. M/s. Adani Wilmar Ltd., Gujarat
35. M/s. Libra Foams, Gautam Buddha Nagar (UP)
36. M/s. Shri Ramchandra Straw Products Ltd., Moradabad (UP)
37. M/s. Bilag Industries Pvt. Ltd., Gujarat
38. M/s. Daurala Organics Ltd., New Delhi
39. M/s. C.J. Shah & Company, Mumbai
40. M/s. Hareesh Kr. & Company, Mumbai
41. M/s. Lamproa Chem. & Ind. Limited, Gujarat
42. M/s. Hindustan Ink & Resins Ltd., Gujarat

Response/information to the questionnaire/notification was filed by the following exporters/producers:-

1. M/s. Solvay Brussels, Belgium

Response/information to the questionnaire/notification was filed by the following Importers/user Associations.

1. M/s. NALCO, Bhubaneswar
 2. M/s. Hind Lever Chemicals Ltd., Mumbai
 3. M/s. Hindustan Lever Ltd., Mumbai
- xii) Information regarding injury was sought from the petitioner(s), which was also furnished by the petitioner. The injury parameters of the following domestic producers were furnished:-
1. M/s DCW Limited, Mumbai
 2. M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., Vadodara
 3. M/s Search Chem. Industries Ltd., Mumbai
 4. M/s Grasim Industries Ltd., Nagada (MP)
 5. M/s.SIEL Chemicals Complex, Punjab
 6. M/s Bihar Caustic & Chemicals Ltd.. Bihar
 7. M/s Jayshree Chemicals Ltd, Orissa
 8. M/s Andhra Sugars Ltd., Tanaku
 9. M/s. Indian Petro Chemicals Corporation Ltd., Dahej
- xiv) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- xv) The cost of production of the domestic industry was also analysed to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) based on the information furnished by petitioner so as to ascertain if anti dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to domestic industry. The cost of production data of the following companies were considered and examined appropriately:--
1. M/s DCW Limited, Mumbai
 2. M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., Vadodara
 3. M/s Search Chem. Industries Ltd., Mumbai
 4. M/s Grasim Industries Ltd., Nagada (MP)
 5. M/s.SIEL Chemicals Complex, Punjab
 6. M/s Bihar Caustic & Chemicals Ltd.. Bihar
 7. M/s Jayshree Chemicals Ltd, Orissa
 8. M/s Andhra Sugars Ltd., Tanaku
 9. M/s. Indian Petro Chemicals Corporation Ltd., Dahej
- xvi) ****in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xvii) The last date of submission was 28th November, 2002. On request of interested parties, extension of time was granted upto 10th December, 2002. Incomplete response of one of the importer M/s. NALCO was received on 18th December 2002, which has also been considered by the Designated Authority.

- xviii) Investigation was carried out for the period starting from 1st January to 30th September 2002 i.e. the period of investigation (POI).
- xix) Additional details regarding injury were sought from the petitioner, which were also furnished.
- xx) The Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry to the extent considered necessary.
- xxi) Copies of initiation notice was also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc., for wider circulation.

B. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

1. PETITIONER'S VIEWS

a) PRODUCT UNDER CONSIDERATION :

- (i) The name of the product being dumped into the Indian market is Sodium Hydroxide generally known as Caustic Soda. Caustic Soda is chemically known as NaOH. It is an Inorganic Chemical classified under Chapter 28 of the Custom Tariff Act. Caustic Soda is a soapy, strongly alkaline odourless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. It is mainly used in the manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, vanaspati, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms- lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form. All forms of caustic soda are the subject matter of the present petition.

Caustic Soda causes burn on contact with body tissues. Contact with eyes causes severe damages, swallowing results in severe injury. Caustic soda mist causes momentary stinging sensation in nose and throat. It reacts with strong acid very violently under boiling phenomena.

- (ii) Caustic Soda is a basic product very widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. It is mainly used in the manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, vanaspati, petroleum refining.
- (iii) Three technologies are available world over for production of Caustic Soda. The Indian industry is producing Caustic Soda using all the three processes. The three processes are:
 - ❖ Mercury Cell Process
 - ❖ Diaphragm Process
 - ❖ Membrane process

Mercury cells process: In mercury process cells Titanium Metal anodes are being used as anodes and mercury as cathode. Salt is added to saturators where depleted brine from the brine dechlorination tower is coming to get saturated. The concentration of depleted brine is around 260 gpl of NaCl. The depleted brine enters the saturators packed with salt and over flows from the other side after getting saturated to a concentration of 310 gpl of NaCl. From the saturators the saturated brine travels to two purifiers. Where Lime (Calcium hydroxide) and Sodium Carbonate is added to precipitate the impurities then travels to the settler, where all the precipitates settle, and clarified brine over flows from the settler to the clarified brine tank. The precipitated impurities, which are collected at the bottom of the settler, are taken out from the bottom valve and thrown into the sludge pit where the same is allowed to settle further and the supernatant brine is recovered.

The clarified brine which is collected in Tank is then pumped to pure brine storage tank through filters. From this storage tank pure brine is pumped to overhead tank located at a height of above 11 meters. From this overhead tank pure brine is continuously fed to the cells in the Cell House where by electrolytic process sodium Chloride is decomposed and from caustic soda and chlorine gas and Hydrogen gas. Caustic soda from through heat exchanger the same is pumped to Caustic soda storage tank.

The decomposed brine which comes out of the cells is called depleted brine. The part of the Sodium Chloride gets decomposed to form Caustic Soda. When the brine is passing through the cells, its sodium chloride concentration goes down from 310 gpl to 260 gpl. The depleted brine which contains same traces of chlorine is then sent to brine dechlorination tower where by vacuum dechlorination, it is stripped off the chlorine gas and after that it is sent to saturators for restoration. The chlorine gas which is generated in the cells is driven by a blower to chlorine cooling area. Here the gas is cooled and bulk of the moisture is removed. After cooling, the gas is sent to chlorine drying where the remaining moisture is removed by contacting the chlorine gas with sulphuric Acid in drying tower. The gas coming out of drying towers is free from moisture and the same in turn is sent to Chlorine compressor where it is compressed to a pressure of about 3 kgs/cm². After compression the gas is sent to Liquefaction where it is liquefied at a temperature of about - 10-degree C. The liquefied gas is then sent to the Liquid Chlorine storage tank.

Hydrogen gas which is also generated in the Cell House is collected in the Hydrochloric Acid holder.

From the gas holder hydrogen is blown to the Hydrochloric Acid Plant where the gas is burnt with chlorine in Hydrochloric Acid furnaces to make Hydrochloric Acid. The 33% concentrate Hydrochloric Acid from the furnace flows to intermediate Hydrochloric Acid receiver tank from where it is sent to Hydrochloric Acid storage tank.

Membrane cell consists of cell elements. Each cell element is made up of anode and cathode assembly separated by means of Membrane cell.

Pure brine is fed to anode compartment through inlet nozzle under electrolytic condition salt (NaCl) gets splitted into Na^+ and Cl^- ions. The Na^+ ions travel through

Membrane element into cathode compartment. Claim: ion evolves Cl_2 gas from anode compartment.

Dilute Caustic is fed to the cathode compartment through inlet nozzle here, H_2O gets splitted into H^+ and OH^- ions the OH^- ions combines with Na^+ ions (from anode compartment) thereby produces Caustic H^+ ions evolves as H_2 gas from cathode compartment. Hydrogen from cell is cooled and sent to H_2 gas.

Chlorine from cells is cooled and dried in chlorine treatment section. The dry chlorine is then compressed and sent to the liquifier where it is liquefied. This chlorine is taken to liquid chlorine storage tank by gravity and packed in one tonne capacity container for sale. Further the excess chlorine gas which is not liquefied is sent to HCL section where Cl_2 gas is burnt with Hydrogen and it is mixed with water to make Liquid Hydrochloric Acid (HCL)

Membrane process:- In the process of manufacturing Caustic Soda with membrane Process, the main raw material required is salt and other important input is power.

Lean brine (salt solution) returning from the process plant is saturated in saturators by adding salt. This saturated brine is treated to remove impurities in primary and secondary brine treatment sections. The desired ultra purity of the brine is achieved in secondary brine treatment by means of ion exchange columns. Ultra pure brine is fed to anode compartment of the membrane cell. The cell consists of two compartment separated by membrane. One compartment is called cathode and other compartment is called as anode. Dilute Caustic is fed to cathode compartment. Concentrated Caustic is collected from the cell as the main product. The lean brine from the cell is sent back to saturators after dechlorination.

Caustic Soda, Chlorine and Hydrogen is produced in Membrane Cell by ion exchange Membrane process using selective ion exchange properties of the Membrane, which is the main component of the Membrane Cell.

A Membrane Cell consists of cell elements. Each cell element is made up of anode and cathode assembly separated by means of Membrane Cell.

Pure brine is fed to anode compartment through inlet nozzles under electrolytic condition salt (NaCl) gets splitted into Na^+ and Cl^- ions. The Na^+ ions travels through Membrane element into cathode compartment. Cl^- ions evolves as Cl_2 gas from anode compartment.

Dilute Caustic is fed to the cathode compartment through inlet nozzles. Here, H_2O gets splitted into H^+ and OH^- ions. The OH^- ions combines with Na^+ ions (from anode compartment) thereby produces Caustic H^+ ions evolves as H_2 gas cathode compartment. Hydrogen from cell is cooled and sent to H_2 gas holder.

Chlorine from cells is cooled and dried in chlorine treatment sections. The dry chlorine is then compressed and sent to the liquifier where it is liquefied. This liquid chlorine is taken to liquid chlorine storage tank by gravity and packed in one tonne capacity

container for sale. Further the excess chlorine gas which is not liquefied is sent to HCL section where CL_2 gas with Hydrogen and it is mixed with water to make liquid Hydrochloric Acid.

- (iv) Even though all three technologies are being used in India for manufacturing Caustic Soda, Mercury Cells technology and Membrane Cells technology are being widely used in India.
- (v) Indian Caustic Soda industry has been largely able to meet entire requirement of Caustic Soda in India. The Indian industry was self-sufficient in its requirement ever since 1975. As mentioned in previous para, Caustic Soda has been in the list of imports permitted under OGL particularly for actual users since 1980-81. The imports were, however, limited because of the pricing policy of the Indian industry. The capacities installed by the producers in Chinese Taipei, Indonesia, and EU(excluding France) are far higher than the requirement in their own country. Further, with the imposition of anti-dumping duties on a number of other countries, the producers in the subject countries are finding it lucrative to export to India. The excess capacities in these Countries have put tremendous pressure on the producers to look for markets outside their country. Resultantly, the exporters from Chinese Taipei, Indonesia and EU (excluding France) have quoted very low prices for exports to India. It would also be relevant to point out that the producers in these countries have at times not directly offered for supplies to India. Substantial volumes have been offered by traders in third countries for supply of Caustic Soda originating in these Countries. The offers being by traders, naturally, these traders have taken care of their margins also. The prices quoted by the producers in these Countries are; therefore, still lower. The petitioners believe that the prices offered are far below the associated cost of production. Thus, the exporter from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France) has resorted to dumping of Caustic Soda in the Indian market.
- vi) Producers in Indonesia, Taiwan, Belgium and Italy are involved in dumping the goods in India. The supplies are planned directly from these countries. Belgium and Italy are members of European Union. There are producers of Caustic Soda in other member countries of the European Union. There are no custom boundaries in the European Union between the various member countries. Prices in the whole of the European Union can be expected to be in the same region. Imposition of anti dumping duty cannot be effective without imposing duty against European Union as a whole as dumping may start from other sources after imposition of anti dumping duty against Italy and Belgium. In fact, there is Anti Dumping Duty in force against one of the member countries of European Union, i.e. France. After imposition of anti dumping duty against France, exporters from Italy and Belgium have exported Caustic Soda in the Indian market at dumped prices. Petitioners therefore, request the Designated Authority to initiate investigations against European Union. However, since France is already covered under existing measures, investigations may be restricted to the European Union, excluding France.

b) DOMESTIC INDUSTRY

The petition filed by the M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) representing the domestic industry, has been supported by M/s DCW Limited, Mumbai, M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, Vadodara, Gujarat, M/s Search Chem Industries Limited, Mumbai, M/s Grasim Industries Ltd, Nagda, M.P., M/s SIEL Chemical Complex, Patiala, Punjab, M/s Bihar Caustic & Chemicals, Ltd., Jharkhand, M/s Jayshree Chemicals Limited, Orissa, M/s Andhra Sugars Limited, Tanaku, DCM Sriram, New Delhi, M/S Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara, M/S Standard Alkali, Mumbai and M/S DCM Sriram Consolidated Ltd., New Delhi. The petitioner companies constitute 55.67% of the subject goods production and thus have the standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry.

- (i) DCW Limited a multi product company involved in production of various products such as Soda Ash, Caustic Soda (Lye, Solid and flakes), Calcium Chloride, Soda Bicarbonate, Aluminum Bicarbonate, Salt etc.
- (ii) Gujarat Alkalies & Chemicals Limited is also a multi- product company involved in production of wide range of products which include Caustic Soda, Chlorine Gas, Hydrochloric Acid, Hydrogen gas, Sodium Cyanide, Sodium Hydrochloride, Sodium Ferrocyanide, Methyl Chloride, Chloroform, Carbon Tetrachloride, Potassium Hydroxide, Potassium carbonate, Phosphoric Acid, Hydrogen Peroxide etc.
- (iii) Search Chem. is a subsidiary of United Phosphorus Limited. SCIL is a multi product company involved in production of various chemicals such as Yellow Phosphorus, Iso Propyl Bromide, Thio di Phenol, Methylene Glutaronitrile, Acetyl Bromide, Para Nitro Benzyl Alcohol and Triphenyl Phosphorus Thionate etc. The company is also involved in production for Power i.e. Electricity.
- (iv) Grasim Industries Limited is a flagship company of Aditya Vikram Birla Group. Grasim Industries Limited is a multi product, multi location and well diversified company involved in production of various products such as Viscose Staple fibre, White Cement, Sulphuric Acid, Carbon Domestic industry Sulphate, Rayon grade pulp, Paper, Stable Bleaching Powder, Man Made Fibre Fabrics, Man Made Fibre Yarn, Gray Cement, Articles of Cement Concrete, Industrial Machinery, Poly Aluminum Chloride, Chloro Sulphonic Acid, and Sponge iron, etc.
- (v) Andhra Sugars Limited is a multi product, multi location company involved in production of Sugar, Acetic Acid, Industrial Alcohol's, Sulphuric Acid, Superphosphate, Chlorosulphonic Acid, Oleum, Aspirin, Carbon Dioxide, Alum, Diffusers, Chemical Equipment, Sugar Factory Boiling House Equipment's, Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine, Cotton Seeds etc, Richburn and oil cakes processing, Refinery, Hydrogenation of oils, cattle and poultry feed, wind power, electricity, etc.
- (vi) Bihar Caustic, Jayshree Chemicals, and SIEL (Chemical Complex) are involved in production of Caustic Soda and it's by-products only.

- (vii) M/s. IPCL is a multi product company, and its products are Ethylene, Propylene, Butadiene, Butene-I, Benzene, Cixon, Carbon Black feedstock, Acrylonitrile, Indothene, Indothene LL/Indothene HD, Koylene, Koylene CP, Koylene ADL, Indovin, Cisamer, Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, Indacrl, Supacryl, Acrylates, Petrez, Linear alkyl Benzene, Para Xylene, Ortho Xylene, Solvent CIX, Hepton, Dimethyl Terephthalate, Caustic Soda, Chlorine, Power(MWH)

c) **LIKE ARTICLE**

- (i) There is no difference in the Caustic Soda produced by the Indian industry and imported from China and Korea. Caustic Soda produced by the Indian industry in general and the participating companies in particular is comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, raw material composition, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Caustic Soda produced by the domestic industry should be treated as like article to Caustic Soda imported from subject countries within the meaning of the anti-dumping Rules.
- (ii) As discussed earlier in this petition, world-over, Caustic Soda is being produced by three processes. Indian industry is also producing Caustic Soda using all the three processes. However, difference in process does not mean difference in the product in terms of its physical & chemical properties, product specifications, marketing, pricing, consumer perceptions, tariff classification, etc.

d) **DUMPING**

- (i) Producers from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France) are involved in dumping the goods in India. The dumping has been largely resorted through traders in third Countries. However, the supplies were planned directly from these Countries.
- (ii) Caustic Soda is a basic inorganic chemical and is used by a number of industries as raw material. It is primarily traded in bulk quantity and, therefore, the shipments are normally directly from the countries of origin. However, in the instant case and particularly in the tender floated by NALCO for purchase of very significant volumes, traders in third Countries have participated wherein the supplies have to be made directly from the subject countries.
- (iii) NALCO had recently floated a tender for 115000 MT of Caustic Soda. A number of exporters participated in the tender floated by NALCO. The quantity of the tender floated is very significant.
- (iv) Exporters from subject countries as well as other country against which investigation is under progress or which are now attracting duties participated in the tender. Details of the tender floated, exporter's name, agent's name, quantity offered, price offered, revised price offered, negotiated price at which order has placed by NALCO, landed value of imported material etc. are given in the "tender detail".

- (v) Recently, one of the major consumers M/s. NALCO has floated a global tender for 115000 MT Caustic Soda. One of the conditions of this tender is under,

"In the event of imposition of Anti Dumping Duty by Government of India after placement of order, the supplier will make all attempts to source supply from other non Anti Dumping origin at the same price and terms and conditions of the order. Time allowed by buyer for arranging material from non Anti Dumping origins from the date of imposition of Anti Dumping Duty by the Government of India will be 30 days. However, if the seller fails to make supply as per above, the buyer reserve right to terminate the order for the balance contract quantity without financial liability on either side. This will not cover for the shipment, which are in transit."

- (vi) Exporters and producers from Indonesia, Taiwan and European Union are dumping Caustic Soda in the Indian market. It is the market information of the domestic industry that significant material is shortly landing at the various custom ports in India. It would be worthy to mention here than the domestic industry had earlier twice filed a petition for imposition of anti dumping duty inter-alia on Indonesia. However, the investigations were not initiated against Indonesia. Getting benefit of the situation i.e. imposition of Anti Dumping Duty against some other countries and no duty on imports from Indonesia, the producers and exporters from Indonesia have now found this a good opportunity to dump the material at times of serious decline in the export price from several countries and faced with surplus unutilized capacity.
- (vii) It may be seen that NALCO has placed its orders for 115000 MT, which is more than combined imports of Caustic Soda in a year in India.
- (viii) Efforts were made to get information on prices at which Caustic Soda is being sold by the exporters in their domestic market. We have been able to get information about the prices in domestic market of Belgium in particular and European Union in general from a leading International Journal. Reliance is being placed on the information published in the Chlor Alkali in this regard. Chlor alkali regularly reports the prices of Caustic Soda in the domestic market in European Union. Thus, considering the prices given in the Chlor Alkali, calculation of normal value in exporting country have been done.
- (ix) Efforts were made to get information on prices at which Caustic Soda is being sold by the exporters from Indonesia and Taiwan in their domestic market. Petitioners have been able to get information about the prices in domestic market of Indonesia and Taiwan from a leading international Journal. Reliance is being placed on the information published in the Chlor Alkali in this regard. Chlor Alkali regularly reports the prices of Caustic Soda in the domestic market in Indonesia and Taiwan. Thus, considering the prices given in the Chlor Alkali, calculation of normal value in these countries have been done.
- (x) Massive dumping of Caustic Soda in the Indian market is causing material injury to the domestic industry. Further, the order placed by NALCO would cause

further material injury to the domestic industry, as may be seen from the para on "Evidence of Injury".

e) **INJURY**

- (i) The Rule on threat of injury states that "determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of injury, the Authority shall consider, inter-alia, such factors and:-
 - (a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - (b) sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - (c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - (d) Inventories of the article being investigated."
- (ii) It is understood that the capacity of producers in subject countries is far in excess of the domestic demand in their respective markets. The huge volume of material offered to NALCO is a clear evidence in this direction. The producers are under tremendous pressure to sell the material. Vast Indian market is naturally quite lucrative to the exporters at the cost of Indian Producers.
- (iii) The exporters are understood to have booked orders for significant quantity through their Indian agent/s. In fact, orders for 115000 MT is being placed by NALCO, (for which tender was placed earlier) which alone is more than average annual imports of Caustic Soda in India as also capacity of a number of individual producers in India.
- (iv) Our market intelligence suggests that a lot of dumped material is under transit and shipment is expected very shortly. Should the present trend of order booking continue, the domestic industry would loose significant sales.
- (v) The landed price of the imported material is significantly below the selling prices of the domestic industry. The volume of material for which order has booked is very significant in terms of demand of the subject product in India. Moreover, what should be appreciated is that should the producer in subject countries continue to sell the material at present prices in the Indian market, the domestic industry would not be able to hold even the present prices.
- (vi) The landed price of imports is significantly below the full cost of production and fair selling price of the domestic industry. The domestic industry would be forced

to face cash losses in case it has to sell at matching prices. The order placed by NALCO has had severe depressing effect on the prices in the market, more so in the post proposed investigation period.

- (vii) The dumping margins are very significant. The price at which material is being exported does not permit recovery of even cost of production leave alone profits on huge investments.
- (viii) In the instant case:-
 - a) There is a history of dumping. Earlier the domestic industry has been injured from dumping of Caustic Soda in India by the exporters/ producers from Saudi Arabia, USA, Japan, Iran and France. The domestic industry requested the Designated Authority to impose Anti Dumping Duty. The Designated Authority, after a detailed investigation, recommended imposition of Anti Dumping Duty, which have since been imposed by the Central Government. After imposition of Anti Dumping Duty against these countries, producer/exporter from Qatar started dumping Caustic Soda in India. The domestic industry requested the Designated Authority to impose Anti Dumping Duty against Qatar also. The Designated Authority after preliminary investigations, recommended imposition of provisional duty. After initiation of the investigation against Qatar, producers and exporters from subject countries started dumping the material. Thus, there is a clear history of dumping of Caustic Soda in India by now.
 - b) The importers are well aware that the price at which the material is being exported from subject countries is a dumped price as the price is significantly below the reference price fixed by the Designated Authority in the earlier investigation. Evidently, the importers and consumers are well aware that the material is being imported at dumped prices;
 - c) The injury is being caused by the producers/exporters from subject countries in a short period. Immediately after imposition of duty against Saudi Arabia, USA, Japan, Iran, France and Qatar the producer in subject countries started dumping. Our market intelligence suggests that the exporter have booked huge orders, which are under process of exportation.
 - d) Sales to the tune of about 115,000 MT have been lost by the domestic industry in a single order as the prices quoted by the exporters from these sources is much lower than quotations by Indian producers in the recent tender floated by NALCO.
 - e) The Sales volumes of the participating companies as provided to the Authority indicate that sales of the participating companies, which were more or less stagnant till 2001, declined in the period first two quarters of calendar year 2002. Further, the sales volumes of some of the participating companies are likely to decline further due to present tender of 115000 MT by NALCO.
 - f) The imports of Caustic Soda from the subject countries have increased dramatically. From a situation of off-and-on imports, the imports made by NALCO alone would be more than the combined volume of imports from all the

countries and capacities of many a producers in the Country. Further, dramatic increase in imports has resulted in significant increase in share of imports in (a) imports of Caustic Soda in India; and (b) demand of Caustic Soda in India.

- g) The production of the participating companies, which has been increasing till 2000-01 declined in the April-December 2001. Moreover, the petitioners submit that the change in the production level alone may not indicate injury to the domestic industry. More important parameter is the price at which offers for sale have been made by the exporters from the subject countries and the prices at which the domestic industry has been forced to sell or may be forced to sell in view of the dumped imports from the subject countries.
- h) Caustic Soda industry has provided very large-scale employment in the Country. Any sickness in the industry would have crippling effect on the employment.
- i) The petitioners have lost significant sales due to the dumped imports. The loss of the NALCO order is a significant loss of sales for the domestic industry.
- j) Profitability of the participating companies has endorsed and domestic industry is causing huge losses.
- k) Imports of Caustic Soda from Other Countries (excluding countries already attracting anti-dumping duties or countries against which investigation is under progress), are de-minimus or are at a price not causing any injury to Indian industry.
- l) Demand of the Caustic Soda is increasing continuously. In fact, the demand has registered significant growth over the past five years. The domestic industry has sufficient capacity to meet the requirement of the Country. The changes in the demand have, therefore, not contributed to any injury to the domestic industry.
- m) Material injury has been caused to domestic industry from dumped imports from the subject countries. As stated elsewhere in the petition also, the domestic industry is producing Caustic Soda for the several years. The technology adopted by the domestic industry is comparable to the technology adopted by the exporters. There is no significant difference in the manufacturing process. It is submitted that the lowering of prices by the exporter from the subject countries alongwith the dumped imports from Other Countries (which are already attracting duties are against which the investigations are in progress) is the reason for the present injury to the domestic industry.
- n) The imports of Caustic Soda from countries other than subject country excluding those countries where anti dumping duties are already in place, are almost negligible or are de-minimus are not causing any injury to the Domestic Industry. The changes in demand have not contributed any injury to the Domestic Industry.

2. IMPORTER'S VIEWS

M/s. NALCO, Bhubaneswar has responded to the Initiation Notification in the importers questionnaire but without the details regarding dumping, injury and causal link etc.

M/s. Hindustan Lever Ltd., Mumbai has also responded to the Initiation Notification in the importers questionnaire but without the arguments against dumping, injury and causal link etc.

M/s. Hind Lever Ltd., Mumbai furnished the detailed information in the importers questionnaire but without the arguments against dumping, injury and causal link etc.

3. **EXPORTER'S VIEWS**

M/s. Solvay Brussels Belgium has responded to the initiation notification but without the information in the exporters questionnaire and supplied only four pages of the non confidential submission which is otherwise incomplete.

M/s. BASF Antwerpen N.V.(Belgium) has initially requested for extension for filing the exporters questionnaire and the Authority duly considering their request has accepted the request of extension to file exporters questionnaire by 10th December 2002 but, vide the letter dated 7th November 2002, informed that they have not exported the product under investigation directly or indirectly into India during the period of investigation and before.

M/s. BASF AG Ludwigshafen (Germany) has also informed that they have not exported the product under investigation directly or indirectly into India during the investigation and before.

M/s. Bayer Shell Isocyanates N.V. expressed that they have not exported the product under consideration directly or indirectly into India during the investigation and before.

C. **EXAMINATION AND FINDINGS BY AUTHORITY**

The submission made by the imports, exporters, users, domestic industry and other interested parties have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter.

The cases of new exporters of those stated to be willing to give price undertaking shall be considered, on request by the Authority in accordance with the Rules Supra.

Some of the Exporters/manufacturers have claimed that they have not exported to India during the period of investigation. It has been the practice to allow these exporters to apply for review as new exporters under Rule 22 of Anti Dumping Rules mentioned above as and when they export to India.

1. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France). Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn,

staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc.

Caustic soda is classified under chapter 28 of the customs Tariff Act, 1975 under Customs Head 2815.11 and 2815.12. As per ITC Eight Digit classification, the product is classified under the Custom Heading 2815.1101, 2815.1102 and 2815.1200. The classification, is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Caustic soda is produced in two forms, i.e. lye and solids by three technology processes, i.e mercury cell process, diaphragm process and membrane process. Caustic Soda can be imported under OGL and attracts a basic customs duty of 30%. The present investigation covers all forms of caustic soda.

The Authority notes that the investigation covers all forms of caustic soda both Lye and flakes, and all different forms of the same subject goods are used substitutably depending on the requirement of the user. The two forms in various concentrations are therefore the subject matter of the investigation. The Authority further for the purposes of dumping margin has made appropriate comparisons on DMT basis only.

2. LIKE ARTICLE

The Authority notes that the petitioner has claimed that the goods produced by them are like article to the goods produced, and exported from the subject country. Also both are technically and commercially substitutable and the consumers are using the domestically produced and imported goods interchangeably. It has been indicated that the Caustic soda is processed by three processes viz. Mercury cells process, diaphragm process and membrane process world over. The difference in these processes does not mean difference in product in terms of various characteristics. Also there is no significant difference in the cost of production for the three processes. The petitioner has claimed that the goods produced by them and those exported from the subject countries are like article within the meaning of the Rules.

The Authority in view of submissions made by other interested parties and keeping in view the substitutability and interchangeability of the goods exported from subject countries and those produced by the Domestic Industry, considers the subject goods exported and the domestically produced subject goods as like article as per Rule 2(d) for the purpose of preliminary determination pending final determination.

3. DOMESTIC INDUSTRY

The petition has been filed by M/s. Alkali Manufactures Association of India (AMAI), Delhi on behalf of the domestic industry. The Association represents most of all the domestic manufacturers of Caustic Soda in India. The petition has been expressedly supported by the following domestic producers, i.e. M/s. DCW Ltd., Mumbai, M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., Baroda, M/s. Search Chem. Industries Ltd., Mumbai, M/s. Grasim Industries Ltd., Nagada (MP), M/s. SIEL Chemical Complex, Punjab, M/s. Bihar Caustic & Chemicals Ltd., Jharkhand, M/s. Jayshree Chemicals Ltd., Orissa and M/s. Andhra Sugars Ltd., Tanaku,. These petitioners companies represents 40.09% of the subject good under production and with support

M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara, M/s. Standard Alkali, Mumbai, and M/s. DCM Shriram Consolidated Ltd., New Delhi they represent 55.67%.

The Authority also notes that the domestic producers who have supported the petition constitute more than 50% of the total domestic production and therefore have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5 (3) (a) and (b) of the Anti-Dumping Rules and also represent Domestic Industry in terms of Rule 2(b)

4. NORMAL VALUE & EXPORT PRICE

Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The normal value and ex-factory export price determination is illustrated below.

EUROPEAN UNION (EXCLUDING FRANCE)

A. NORMAL VALUE

The Authority sent questionnaires to all known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A (1)(C). M/s. BASF, Belgium, M/s. BASF, Germany, M/s. Bayer Shell Isoyanates, N.V., Belgium have stated that they have not exported to India during the period of investigation. M/s. Solvay Belgium have filed the incomplete four pages reply to initiation notification without giving the details in the prescribed exporters questionnaire.

In view of the inadequate and incomplete response filed by the exporters from European Union(excluding France) the Authority has relied on the information provided by the domestic industry for the purpose of preliminary finding. However, the information furnished by the exporter shall be taken into account after the complete and full information required as per the questionnaire, is furnished. In view of this the Authority has constructed normal value for all producers/exporters on the basis of data provided by the petitioner in the domestic market of EU(excluding France) through secondary sources from leading international journal i.e., Chlor Alkali with due adjustments for the subject goods in EU(excluding France).

The Authority has referenced the Normal Value for such producers/exporters as ****\$/DMT.

B. EXPORT PRICE

The Authority notes that the export price has been provided by the petitioners on the basis of the data collected by them from DGCI&S. The petitioners have also claimed adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, port expenses and inland freight to an extent of ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT and ****\$/DMT respectively.

The ex-factory export price is referenced as ****\$/DMT.

INDONESIA

A. NORMAL VALUE

The Authority notes that none of the exporters from Indonesia have responded by way of questionnaire response to the initiation notification. The Authority in view of non-cooperation has constructed normal value for all producers/exporters of Indonesia on the basis of best available information as furnished by the petitioner. In view of this the Authority has constructed normal value for all producers/exporters on the basis of data provided by the petitioner in the domestic market of Indonesia through secondary sources from leading international journal i.e., Chlor Alkali with due adjustments for the subject goods in Indonesia.

The normal value is therefore referenced as ****\$/DMT for Indonesia for the purpose of preliminary determination pending final determination.

B. EXPORT PRICE

The Authority notes that the export price has been provided by the petitioners on the basis of the data collected by them from DGCI&S. The petitioners have also claimed adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, port expenses and inland freight to an extent of ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT and ****\$/DMT respectively.

The ex-factory export price is referenced as ****\$/DMT.

CHINESE TAIPEI**A. NORMAL VALUE**

The Authority notes that none of the exporters from Chinese Taipei have responded by way of questionnaire response to the initiation notification. The Authority in view of non-cooperation has constructed normal value for all producers/exporters of Chinese Taipei on the basis of best available information as furnished by the petitioner. In view of this the Authority has constructed normal value for all producers/exporters on the basis of data provided by the petitioner in the domestic market of Chinese Taipei through secondary sources from leading international journal i.e., Chlor Alkali with due adjustments for the subject goods in Chinese Taipei.

The normal value is therefore referenced as ****\$/DMT for Chinese Taipei for the purpose of preliminary determination pending final determination.

B. EXPORT PRICE

The Authority notes that the export price provided by the petitioner on the basis of data collected by them from secondary prices. The petitioner have also claimed adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, inland freight, port expenses to an extent of ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT and ****\$/DMT respectively. The Authority further notes that the transaction wise data received from DGCI&S for the period (January-July) 2002, is not showing any imports from Taiwan whereas M/s. NALCO one of the cooperating importers, has shown the import from Chinese Taipei to the extent of 26189 MT upto April 2002. The Authority in this regard notes, the evidence provided by the petitioner which indicates the offer was also made by the importer in India in the POI. The petitioner has claimed that M/s. NALCO had floated the tender on 8th July 2002 and the price bid was opened on 13th August 2002 and order was placed to two foreign parties to supply of Caustic Soda originating in Taiwan. The orders for 30000 MT was placed to M/s. Nissho Hawai @ US\$ ****/ PMT and 56000 MT @ US\$ ****/ PMT was placed to M/s. Angulf Polymers and Chemicals The Authority in this regard notes that the date of selling could be date of contract, purchase order, order confirmation, or invoice whichever establishes the material terms of sales. The Authority in view of the available evidence and information provided by the petitioner notes that the exporter has indicated an export price pertaining to the shipment made to India as ****\$/DMT. The petitioners have also claimed adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, port expenses and inland freight to an extent of ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT and ****\$/DMT respectively.

The ex-factory export price is referenced as ****\$/DMT.

5. DUMPING-Comparison of Normal Value & Export Price

The rules relating to comparison provides as follows:

“While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits,

for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability.”

The authority has carried out normal value comparison with the weighted average ex-factory export price in Period of Investigation, for evaluation of the dumping margin for all the exporter/producers of the subject country.

The dumping margin for exporter/producers comes as under:

Sl. No.	Country/ Exporter/Producer	Normal Value (\$/MT)	Ex-Factory Export price (\$/MT)	Dumping Margin as % of EP
1	EU(excluding France) All exporters/producers	****	****	489.36%
2	Indonesia All exporters/producers	****	****	299.87%
3	Chinese Taipei All exporters/producers	****	****	58.79%

6. INJURY AND CAUSAL LINK

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, “.....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY

It is observed from the facts available on record that the margins of dumping from each of the subject countries are more than the 2% limit expressed as % of export price. Also the volumes of imports from each of the country are more than de minimus. Cumulative assessment of the effects of imports would be appropriate since the exports from the subject countries directly compete with each other and with the goods offered by the domestic industry in the Indian market. The Authority, therefore, proposes to assess injury to the domestic industry from the subject countries cumulatively.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

As regards the threat of injury, the Authority notes that the Anti-Dumping Rules states as follows:

“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the DA shall consider, inter-alia, such factors and;

- a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- b) sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and,
- d) inventories of the article being investigated.

Regarding the threat of material injury the Authority has noted that there is a significant increase of dumped imports during the POI i.e. 151614 MT compared to 5472 MT during 2001-2002. The Authority further notes that these imports from subject countries significantly undercut the prices of the domestic product forcing the domestic industry to sell at unremunerative prices. Further the material is coming at a price much below the selling price of domestic industry and if the domestic industry starts selling at this price, the same would result in huge financial loss to the domestic industry. The order placed by M/s. NALCO in favour of supplies from the subject countries would also result in a loss of significant volume to the domestic industry. The inventory has increased from 3371 MT in 2000-2001 to 9133 MT in 2001-2002 whereas showing a marginal decline during the POI. Therefore the domestic industry is facing a threat of material injury due to dumped imports from subject countries.

The Authority after noting the above submissions holds that the non-injurious price has been evaluated for the various domestic producers by appropriately considering the sales realisation from the related products. Also in order to eliminate inefficiencies, the Authority has normated and benchmarked the best practices on utilisation of raw materials, utilities etc..

As regards the injury which could happen on account of higher cost of production in India, the Authority notes that under the Indian Anti Dumping Rules it is the lesser duty rule which is applied. Further in any event the anti dumping duties cannot exceed the dumping margin. Therefore in any event if injury to Domestic Industry which could exceed the dumping margin it is certainly not addressed under the Rules of the Anti Dumping.

While examining the economic parameters relating to the domestic industry, the injury caused to the domestic industry by the earlier dumping from countries attracting Anti Dumping Duty and countries against which investigation is in progress is also required to be considered. Anti Dumping cases History of caustic soda is as under:

Case	Countries
Case 1	USA, Iran, Japan, France and Saudi Arabia
Case 2	Qatar
Case 3	Korea RP and China

The Authority notes and observes the following economic parameters in the case of domestic producers who have supported the petition:-

	1999-2000 (MT)	2000-2001 (MT)	2001-2002 (MT)	POI (MT)	Annualized (MT)
Imports					
Indonesia	14860	0	4972	50546	67395
Taiwan	0	19033	327	85000	113333
EU (excluding France)	298	19964	173	20216	26955
Subject Countries	15157	38996	5472	155762	207683
Market share in Imports					
Subject Countries(%)	17.47	52.97	13.97	70.50	70.50
Economic Parameters of Domestic Industry (MT)					
Capacity	809800	809800	822300	822300	822300
Production	728526	741555	740192	578000	770667
Capacity Utilization(%)	89.96	92	90.01	93.72	93.72
Domestic Sales	519307	516048	522312	392248	522997
Closing stock	4347	3371	9133.3	8875.88	8876
Unit Cost of Production (Rs./MT)	****	****	****	****	****
Unit selling price(Rs./MT)	****	****	****	****	****
Unit Profit/Loss (Rs./MT)	****	****	****	****	****
Demand	1391534	1409949	1406129	1193596	1591461.5
Market Share in Demand(%)					
Imports	6.23	5.22	2.79	18.51	18.51
Subject countries	1.09	2.77	0.39	13.05	13.05
Other countries	5.14	2.46	2.40	5.46	5.46
Domestic Industry	37.32	36.60	37.15	32.86	32.86
Indian Industry	56.45	58.18	60.07	51.16	51.16
Imports in relation to					

Production of domestic industry (%)					
Imports	11.91	9.93	5.29	38.22	38.22
Subject countries	2.08	5.26	0.74	26.95	26.95
Other countries	9.83	4.67	4.55	11.27	11.27

- a) The imports have increased in absolute terms.
- b) Production of the domestic industry increased by just 5% in the investigation period over 1999-00. The increase in production of the domestic industry is a result of imposition of Anti Dumping Duties on a number of sources. However, rate of increase of imports was far higher than the rate of increase of production of the domestic industry.
- c) Even though the domestic industry was able to increase the capacity utilization, the same did not help the industry in improving its profitability. The profitability rather deteriorated.
- d) The orders placed by NALCO in favour of supplies from the subject countries would result in a loss of significant volumes for the domestic industry.
- e) The imports have increased significantly in relation to production; and consumption in India.
- f) The export price of subject goods from subject countries has declined significantly from 12914 Rs. per MT to as low as 3800 Rs. per MT.
- g) Even after imposition of Anti Dumping Duties against a number of countries, domestic industry is not able to make profits due to dumping from one after another countries. In fact, the profitability of the domestic industry has deteriorated in the investigation period after improving over previous years.
- h) Dumped imports are causing price undercutting, price suppression and price depression in the Indian market resulting in erosion in profitability.
- i) As a result of severe price undercutting, the domestic industry has been forced to reduce the prices very significantly.
- j) Landed price of imported material was significantly below cost of production of the domestic industry.
- k) There has been significant increase in inventory during 2000-2001 but showing a marginal decline during the POI.
- l) Apart from the injury being suffered by the domestic industry, there is a threat of further injury being caused to them on account of dumped imports.
- m) Domestic industry is concerned about the price at which the product is being imported. The price at which the material is being exported is a dumped price. Further, the material is entering the market at prices much below the selling prices of the domestic industry. Should the domestic industry start selling at

matching prices, the same would result in very significant financial losses to the domestic industry.

- n) The domestic industry has no option but to increase wages as per prevailing regulations in the country. However, the wage increases are further adversely affecting the profitability, as the domestic industry is not able to proportionately increase the prices.
- o) Cash Profit of the domestic industry declined significantly in the period of investigation, thus adversely affecting the cash flow situation of the domestic industry.
- p) Productivity, even though increased, did not help the domestic industry in improving the profitability. The profitability rather deteriorated further.

The Authority is led to conclusion that all relevant factors, cumulatively and collectively establish that the domestic industry has suffered the material injury during the period of investigation. The imports are further causing threat of material injury.

7. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

The Authority also holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

The Authority also recognises that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers. Imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

8. LANDED VALUE

The landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

D. CONCLUSIONS:

It is seen, after considering the foregoing, that:

- a) The subject goods in all forms originating in or exported from the subject country have been exported to India below its normal value.

- b) The domestic industry has also suffered material injury.
- c) The imports significantly undercut the price of domestic product forcing the domestic industry to sell at unremunerative prices.
- d) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
- e) The Authority recommends anti-dumping duty on imports of subject goods falling under Chapter 28 originating in or exported from the subject countries.
- f) It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping so as to remove the injury to the domestic industry accrued on account of dumping. Accordingly, it is proposed that provisional anti dumping duties equal to the difference between the amount of Column 3 of the Table below and landed value of subject goods in \$/MT be imposed, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries under Chapter 28 Customs sub-heading 2815.11 and 2815.12 of the Customs Tariff, pending final determination.

1	2	3
Sl.No.	Country/ Exporter/Producer	Amount (US\$/MT)
1.	EU(excluding France) All producers/exporters	271.93
2.	Indonesia All producers/exporters	233.58
3	Chinese Taipei All producers/exporters	271.93

E. FURTHER PROCEDURE

The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- a. The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- b. Exporters, Importers, Petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the despatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
- c. The Authority would conduct verifications to the extent deemed necessary;

- d. The Authority would provide opportunity to all interested parties for oral submissions, for which the date and time shall be communicated to all known interested parties separately;
- e. The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority